फोटो फीचर

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को श्री राम की प्रतिमा भेंट करते हुए

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए

उत्तर प्रदेश संदेश

फरवरी, 2018
वर्ष 29, अंक 2

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
अनुज कुमार झा
सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश

सम्पादकीय परामर्श :
डॉ. ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, अपर निदेशक
हेमन्त कुमार सिंह, उप निदेशक

सलाहकार सम्पादक :
दिनेश कुमार गर्ग, सहायक निदेशक

सम्पादक :
चन्द्र शेखर यादव

सज्जा :
अतुल ग्राफिक्स
76, नया गांव (पूर्व)
एम.एल. बोस मार्ग, लखनऊ

छायाचित्र :
फोटो शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र.

मुद्रक :
पवन कुमार गोयल
अतुल ग्राफिक्स
76, नया गाँव (पूर्व)
एम.एल. बोस मार्ग, लखनऊ

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

इन्वेस्टर्स समिट 01
- बदल रहा है उत्तर प्रदेश .....
- योगी सरकार खींच रही बड़ी .....

आवरण कथा 6
- सौभाग्य की सुनहरी इबारत .....
- निवेशकों का लाल कालीन पर .....

सुधरता परिवेश 20
अपराध पर नियंत्रण से अर्थव्यवस्था .....

बजट 22
- बुनियादी सुविधाओं से खुलेंगे .....
- जो कोई नहीं कर पाया, वह कर .....

फिल्म 29
फिल्म निर्माण का खुला द्वार .....

नीतियाँ 31
विभिन्न नीतियाँ .....

फैसले 33
मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय .....

आजादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश देश का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश रहा है और विशाल भी इतना कि विकास का सफर तय करना प्रदेश के नेतृत्व के लिये हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। जबसे योगी आदित्यनाथ ने यहां सरकार की कमान संभाली है, तबसे उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को एक नयी कार्य संस्कृति से लैस करने का अभियान छेड़ दिया है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिये सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था होती है। योगी राज ने प्रदेश की इस दुखती रग पर सबसे पहले हाथ रखा। सुशासन का आधार ही इस बात पर टिका होता है कि राज्य का हर छोटा या बड़ा आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वर्तमान सरकार के 11 महीने के कार्यकाल में हालात में सुधार दिखाई पड़े, विकास की हलचल सुनाई पड़ने लगी। लोगों को भरोसा होने लगा कि वो और उनका कारोबार अपराध की काली छाया से बच सकता है।

सीधा सा गणित है कि अगर राज्य में कारोबार बढ़ेगा तो हाथों को काम तो मिलेगा ही राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा तो गरीबों की सेवा करने की सरकार की क्षमता का भी विकास होगा। जिस तरह सूर्य समुद्र का जल सोख कर बादल बनाता है और फिर पूरी धरती पर बरस कर अन्न, धन-धान्य उपजाते हैं, उसी तरह सरकार का भी धर्म होना चाहिये। इस दिशा में पहले जापान और कोरिया के पैटर्न पर 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के विचार सामने लाकर नयी संभावनाओं के द्वार योगी सरकार ने खोले । उसके बाद दुनिया भर के निवेशकों को राजधानी लखनऊ में जुटा कर टीम योगी ने सौभाग्य की नयी इबारत लिखने की कोशिश की है।

सवाल संभावनाओं को समझकर उस दिशा में मजबूती के साथ कदम बढ़ाने का था और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ चली है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां किसानों की बेहतरी भी राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उस दिशा में भी उ.प्र. सरकार ने आते ही वादे के मुताबिक किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त किया और अब उनकी कोशिश है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य कैसे मिले। प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक वर्तमान सरकार न केवल किसान के उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये फसल की खुद खरीद के अभियान में जुटी है, बल्कि यह जतन भी कर रही है कि उसकी उपज बरबाद न हो। फसल को सुरक्षित रखने के इंतजाम या उसके प्रसंस्करण के लिये देश के कई बड़े उद्यमी आगे आ रहे हैं। सही नीति हो, नियत हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। असंभव को संभव करके दिखाया जा सकता हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति के आधार पर ही इस साल के बजट की भी रूपरेखा बनायी गयी है। गांव, किसान, गरीब, बेरोजगार नौजवान सभी के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। कोशिश ये है कि यूपी के नौजवान को रोजगार के लिये दूसरे प्रदेशों में खाक न छाननी पड़े।

'उत्तर प्रदेश संदेश' के इस अंक में विकास के इसी सुनहरे ताने-बाने से आपको रूबरू कराने का प्रयास किया गया है।

बदल रहा है उत्तर प्रदेश

– निरंकार सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'इन्वेस्टर्स समिट-2018' में रखे एक मॉडल का अवलोकन करते हुए

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की पहल पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित 'इन्वेस्टर्स समिट 2018' में देश के जाने–माने उद्योगपतियों ने यहां निवेश की घोषणा की है। इस समिट की सफलता इसका प्रमाण है कि निवेशकों ने महसूस करना शुरू किया कि अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मुख्यमंत्री को यह आयोजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि ऐसी बन गयी थी कि यहां कोई भी उद्यमी उद्योग–धंधा लगाना नहीं चाहता था। खराब कानून व्यवस्था के कारण अपहरण, फिरौती, हत्या के साथ–साथ भ्रष्टाचार और फिर बिजली की कमी के कारण कोई भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का साहस नहीं करता था। यहां के युवक मुम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली में रोजी–रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। उत्तर प्रदेश को विकास में फिसड्डी राज्यों की 'बीमारू श्रेणी' से निकालकर समृद्ध बनाने के लिए योगी सरकार ने यह महासम्मेलन किया। प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाये हैं। पिछले दस महीनों में पुलिस ने आपरेशन क्लीन मुहिम के तहत लगभग ढाई हजार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, उद्यमियों का प्रदेश सरकार पर भरोसा बढ़ा है। सरकार भी प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना चाहती है, जो प्रदेश में नये उद्योग–धंधे लगाकर ही दिये जा सकते हैं। लखनऊ के इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान में 21 एवं 22 फरवरी को आयोजित इस समिट में 4.28 लाख करोड़ रूपये के 1045 करार (एमओयू) पर विभिन्न उद्यमियों ने हस्ताक्षर किये हैं। यह राशि बढ़कर अब तक 4.68 लाख करोड़ हो गयी है।

इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है और यह नजर भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बुन्देलखण्ड में 20 हजार करोड़ रूपये के निवेश से डिफेंस प्रोडक्शन कॉरीडोर की स्थापना का ऐलान किया है। सिर्फ इस कॉरीडोर से ढायी लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। समिट के दूसरे दिन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने, झाँसी में रेल कोच रिफर्निशिगं सेंटर खोलने, फतेहपुर में रेल पार्क बनाकर यहां रोजगार बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने जिस डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान इन्वेस्टर्स समिट में किया, उसे 20,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की घोषणा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झाँसी, महोबा, चित्रकूट से गुजरेगा का यह डिफेंस कॉरिडोर। इसमें ड्रोन, वायुयान और हेलीकाप्टर, असेंबलिंग सेंटर, बुलेट प्रूफ जैकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'इन्वेस्टर्स समिट-2018' में उद्योगपतियों के साथ

को बढ़ावा देने के उपकरण बनेंगे। बिजली के साथ–साथ सड़क, कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे पर प्रदेश सरकार खास ध्यान दे रही है। राज्य के फोकस सेक्टर्स में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, फिल्म, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा नागरिक उड्डयन आदि प्रमुख उद्योग तथा सेवाएं सम्मिलित हैं।

इस समिट में 17 केन्द्रीय मंत्री शामिल हुए। इसका समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। प्रमुख सत्रों के चेयरपर्सन केन्द्रीय मंत्री रहे और इनके साथ इन सत्रों में प्रदेश के सम्बन्धित विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सम्बद्ध क्षेत्र के उद्यमी और निवेश के इच्छुक निवेशक मौजूद थे। समिट के चार सत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे। 'इन्वेस्टर्स समिट' में थाईलैण्ड सहित सात देश पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल हुए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रतन टाटा, मुकेश अम्बानी ओर गौतम अडानी जैसे महारथियों से मुलाकात कर निवेश की जमीन तैयार की। उनके इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अभी तक अमेरिका, जापान, फिनलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, इजरायल जैसे कई देशों के उद्यमी इस इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। इस समिट में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा, ''रिलायंस अगले तीन साल में उत्तर प्रदेश में 10 हजार करोड़ का निवेश करेगा। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान स्मार्ट नौजवान बने। अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले पांच साल में 35 हजार करोड़ का निवेश किया जायेगा। उन्होंने कहा, ''देश की तरक्की में यूपी की अहम भूमिका है। यूपी में रोजगार देने के लिए हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर में निवेश करेंगे। इसके साथ ही गौतम अडानी ने ऐलान किया कि हम यूपी में स्किल डेवलपमेन्ट सेंटर खोलेंगे।''

कुमार मंगलम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वह 1950 से निवेश कर रहे हैं। 'ईज आफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में उत्तर प्रदेश सातवें नम्बर पर है, इसके लिए योगी जी और उनकी टीम को उन्होंने बधाई दी। बिड़ला ग्रुप उत्तर प्रदेश में अलग–अलग क्षेत्रों में 25 हजार करोड़ का निवेश करेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश के विकास में वे लगातार भाग लेते रहेंगे। आनन्द महिन्द्रा ने कहा, ''उत्तर प्रदेश की तुलना प्रदेश से नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है। इस समिट का आयोजन करना ही उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसमें महिन्द्रा ग्रुप आपके साथ है।'' जी एक्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चन्द्रा ने भी यूपी में बड़े निवेश का ऐलान किया है। जी एक्सेल ग्रुप यूपी में 18,750 करोड़ रूपये का निवेश करेगा। टाटा ग्रुप के एन. चंद्रशेखर ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में टीसीएस की उपस्थिति है। इसके साथ ही टाटा मोटर भी यहां हैं। हमारी खुदरा कंपनियों की यहां एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है। हम पूरे क्षेत्रों में यूपी के विकास में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समिट में लगभग 200 कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी निदेशकों को मुख्यमंत्री ने उ.प्र. में अपनी पूँजी लगाकर विकास के साथ कदमताल की अपील की। उन्होंने उद्यमियों को भी भावनात्मक रूप से जोड़ दिया कि प्रमुख उद्योगपतियों की एडवाइजारी बॉडी 'राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड' का गठन किया गया है। जो एमओयू हुए हैं, उनकी देखरेख और क्रियान्वयन वह खुद करेंगे। इस सम्मेलन की

सफलता के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना सहित उनकी पूरी टीम एक महीने पहले से ही प्रयास कर रही थी। इसमें मुख्य सचिव राजीव कुमार, औद्योगिक विकास आयुक्त डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, सहित कई अधिकारियों ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभायी।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार औद्योगिक विकास का माहौल बनानें में जुटी है। प्रदेश के छोटे–बड़े सभी जिलों में बिजली की पहले से बेहतर सप्लाई हो रही है। इससे उद्योग धंधों के विकास की संभावनाएं बढ़ रही है। बिजली के साथ–साथ सड़क, कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे पर सरकार खास ध्यान दे रही है। राज्य के फोकस सेक्टर्स में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, फिल्म, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा नागरिक उड्डयन आदि प्रमुख उद्योग तथा सेवाएं सम्मिलित हैं। प्रदेश के जनपदों में पारम्परिक शिल्पों एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए तथा उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय में वृद्धि के लिए 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। अपनी उत्कृष्ट कलाओं से उत्तर प्रदेश के कुशल कारीगरों की अपनी एक अलग पहचान देश में है। इन उत्पादों के लिए मार्केटिंग, तकनीकी उन्नयन, कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण तथा आसान ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। प्रदेश में सरकार द्वारा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टर्स में स्थापित होने वाले उद्योगों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कई नीतियाँ बनायी गयी हैं। ईज़ आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत बिजनेस रिफार्म ऐक्शन प्लान को 20 विभागों द्वारा लागू कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। 250 करोड़ रूपये से स्टार्ट–अप फण्ड की शुरूआत की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है।

बजट में व्यवस्था

सरकार ने अपने 2018-19 के बजट में उद्योगों और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास पर बड़ी धनराशि की व्यवस्था की है। औद्योगिक निवेश नीति-2012 के लिए 600 करोड़ रूपये और नयी औद्योगिक नीति के लिए 500 करोड़ की बजट में व्यवस्था की गयी है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के आरम्भिक कार्यो के लिए क्रमशः 650 करोड़ एवं 550 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए क्रमशः एक हजार करोड़ एवं 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' को लागू करने के लिए 250 करोड़ रूपये दिये हैं। 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार' योजना के लिए एक सौ करोड़ की व्यवस्था की गयी है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रूपये दिये गये हैं। पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराये जाने के लिए 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए कुल मिलाकर 55 करोड़ रूपये दिये हैं। उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। लोगों में खुशहाली आयेगी। इस तरह जब एक सकारात्मक माहौल बनेगा तो कहीं न कहीं उत्तम प्रदेश की परिकल्पना भी साकार होगी और यही मुख्यमंत्री योगी का सपना है। पर उद्यमियों ने अभी सिर्फ करारों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। उन्हें जमीन पर आने में वक्त लगेगा। उद्यमियों से हुए करार को जमीन पर उतारने के लिए अब उद्योग विभाग, जिलाधिकारियों एवं जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका बढ़ जायेगी। मानव संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन, बाजार हो या पैसा हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश समृद्धि की संभावनाओं का घर है। यदि प्रदेश में सामाजिक चेतना जागृत हो जाए तो चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं।

योगी सरकार खींच रही बड़ी लकीर

विकास के मैप पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक नजर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विगत 21 व 22 फरवरी को आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की 'बड़ी लकीर' खींचकर न केवल विपक्षी पार्टियों, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों के सामने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिद्धांत 'सहयोगी संघवाद, प्रतियोगी संघवाद' को धरातल पर उतार दिया। प्रधानमंत्री के उद्घाटन व राष्ट्रपति के समापन वाली इस समिट में देश के नामी उद्योगपतियों के साथ ही कई देशों के राजदूतों व अनेक केन्द्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक तथा अनेकानेक उद्योगपतियों ने योगी आदित्यनाथ की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अवश्य ही 'उत्तम प्रदेश' बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि ''जब परिवर्तन होता है तो सामने दिखने लगता है। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट का होना, इतने सारे उद्योगपतियों का एकजुट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस समिट से यूपी के विकास की बुनियाद तैयार हो रही है। इस पर 'न्यू उत्तर प्रदेश' की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण होगा।''

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 'यह संयोग है कि प्रदेश सरकार ने 4 लाख, 28 हजार करोड़ रूपए के बजट की व्यवस्था की है और समिट के पहले ही दिन लगभग 500 कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित 1045 एमओयू से 4.28 लाख करोड़ रूपये का निवेश होगा।' उन्होंने आश्वस्त किया कि 'इन सारे एमओयू के क्रियान्वयन के सारे काम वे अपनी निगरानी में करायेंगे' तथा 'इनसे प्रधानमंत्री के न्यू इण्डिया के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी।' योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि अगले तीन साल में वे प्रदेश में हो रहे भारी निवेश से 40 लाख रोजगारों का सृजन करेंगे। समिट में शामिल होने वाले उद्योगपतियों व उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश के वादों पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि शिखर के निवेशकों में अडानी ने 35,000 करोड़, बिड़ला ने 25,000 करोड़, रिलायंस ने 10,000 करोड़, हिंदुजा ने 10,000 करोड़ तथा एस्सेल ने 18,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है। यदि निवेश के क्षेत्रों को देखें तो प्रदेश के विकास के लगभग सभी क्षेत्रों को समाहित करने के प्रयास हुए हैं और भारत सरकार के अनेक विभाग व सार्वजनिक उद्यम इस काम में पीछे नहीं रहे हैं।

सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि इस वर्ष प्रस्तुत बजट में देश के विकास की नई अवधारणा पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने देश में दो 'रक्षा औद्योगिक गलियारों' की स्थापना की घोषणा की थी। इनमें से एक गलियारा उत्तर प्रदेश में बनेगा। प्रधानमंत्री ने

अपने भाषण में बताया कि यह गलियारा आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ व झाँसी होते हुए चित्रकूट तक जायेगा, जिससे बुंदेलखण्ड क्षेत्र को भारी लाभ होगा। उन्होंने आशा जताई कि इस गलियारे में 20 हजार करोड़ का निवेश होगा तथा बड़ी संख्या में प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार तथा खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मधुरा संबंधों का ही नतीजा है कि प्रदेश को विकास का यह अभूतपूर्व अवसर मिला है। समिट के दूसरे दिन पधारीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया कि किस प्रकार उनके मंत्रालय ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री से सम्पर्क कर इस योजना को 18 घण्टे में अमली जामा पहनाया। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण पर भारी निवेश होगा। केन्द्र सरकार इसमें दो लाख करोड़ का निवेश करेगी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार लाजिस्टिक्स सुविधाओं के निर्माण में 2.5 लाख करोड़ का निवेश करेगी। उन्होंने खासकर उल्लेख किया कि नये राजमार्ग के निर्माण से लखनऊ व कानपुर के बीच की दूरी घटकर केवल 40 मिनट रह जायेगी। उन्होंने बताया कि गंगा नदी में जल–परिवहन से ऐसा व्यापक परिवर्तन होगा जिसकी कल्पना भी अभी नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में उल्लेख किया था कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा हवाई अड्डे नहीं हैं पर अब कुशीनगर व जेवर में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के साथ ही प्रदेश के छोटे शहरों में हवाई अड्डे विकसित किये जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर अपने इस सपने की याद दिलाई कि 'हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में उड़ने की सुविधा मिले।' उत्तर प्रदेश इस दिशा में मील का एक महत्त्वपूर्ण पत्थर सिद्ध हो सकता है।

इन्वेस्टर्स समिट के पहले एक विश्लेषक का कहना था कि चारों ओर भूमि से घिरे होने के कारण बड़े पैमाने पर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश के सामने स्वाभाविक बाधा आती है और यह तुलनात्मक रूप से तटीय प्रदेशों से पीछे रह जाता है। लेकिन जब यह समस्या दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। गडकरी ने बताया कि नदी परिवहन के माध्यम से उत्तर प्रदेश समुद्री मार्ग से न केवल देश के अन्य प्रदेशों, बल्कि विदेशों से भी जुड़ जायेगा। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता के साथ ही हस्तकला और कुटीर उद्योगों की भी बहुलता है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार 'एक जिला एक उत्पाद' के साथ ही प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों–एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है। इस क्षेत्र में 504 इकाईयों के लिए 23,000 करोड़ रूपये के निवेश की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश अपनी कृषि संपदा व संसाधानों के लिए भी देश में अग्रणी स्थान पर है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार व खासकर वित्त मंत्री ने किसानों की आय दूनी करने का अपना वादा दुहराया है। इन्वेस्टर्स सम्मेलन में चीनी उद्योग क्षेत्र में 500 करोड़ के निवेश से गन्ना किसानों को भारी लाभ मिलने की आशा है। पारले समूह द्वारा बहराइच में 100 करोड़ तथा डीसीएम श्रीराम द्वारा हरदोई में 200 करोड़ निवेश की घोषणा स्वागत योग्य है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ ने बंद चीनी मिलों को शुरू करवाने तथा नई चीनी मिलें लगवाने पर खास जोर दिया है। केन्द्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस क्षेत्र में 6,000 करोड़ की सब्सिडी देने की अपनी घोषणा पर जोर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना 'मायका' बताते हुए लखनऊ तथा प्रदेश से भावनात्मक नाता भी जोड़ा। समिट में पधारे अनेक उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश से अपने संबंधों की याद दिलाई, जिससे प्रदेश व समिट का आकर्षण बढ़ा है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने बमुश्किल साल बीता है, पर निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश का माहौल बदला है। यह बदलाव खासकर कानून–व्यवस्था के क्षेत्र में दिखाई देता है। संभवतः कानून–व्यवस्था का प्रदेश में निवेश व औद्योगिक परिवेश पर भारी प्रभाव पड़ता है। अतीत में भी प्रदेश सरकारों ने निवेश लोने के प्रयास किये थे, पर यदि उद्योगपतियों का 'फिरौती' के लिए अपहरण होने की घटनायें तथा बदहाल कानून व्यवस्था को मीडिया की सुर्खियों में जगह मिलने लगे तो भला कोई निवेशक क्यों आयेगा? समिट में पधारे केन्द्रीय गृह मंत्री, लखनऊ से सांसद तथा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि ''औद्योगिक विकास के लिए सुरक्षा सबसे कसौटी है। इसके लिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था दुरस्त होना जरूरी है। यूपी में इसके लिये जो शुरूआत हुई है निश्चित तौर पर उसने आने वाले दिनों में यह उद्यमियों के लिए सबसे बड़े फायदे का सौदा साबित होगा।'' उन्होंने औद्योगिक सुरक्षा के लिए नई नीति बनाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश में सीआईएसएफ की भूमिका बढ़ाने का सुझाव दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री की घोषणा से उनकी एक बड़ी चिन्ता दूर हो गई है तथा प्रदेश सरकार औद्योगिक सुरक्षा की नई नीति बनाने में आवश्यक योगदान करेगी।

इन्वेस्टर्स समिट में की गई निवेश सम्बन्धी घोषणाओं को जमीन पर उतरने तथा जनता तक उसके लाभ पहुँचने में कुछ समय लगेगा, पर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाने पहले से ही शुरू कर दिये हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित पूर्वान्चल राजमार्ग के दोनों ओर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून–व्यवस्था सुधारने के साथ ही नौकरशाही मकड़जाल तोड़ने के प्रयास शुरू किये हैं। समिट में की गई निवेश घोषणाओं में हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन पर स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित निगरानी का आश्वासन स्वागत योग्य है।

सौभाग्य की सुनहरी इबारत
में इन्वेस्टर्स समिट

– रजनीकांत वशिष्ठ

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा और कई मायनों में सौभाग्यशाली राज्य है। प्रकृति, अध्यात्म और राजनीति के क्षेत्र में इस प्रदेश ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी ऊर्जा से आलोकित किया है। उद्योग व्यापार के मामले में भी इसका अपना एक सम्मानजनक स्थान रहा है। पर बीते कुछ सालों में लोग ये कहने लगे थे कि यू.पी. तो बिहार से भी गया बीता हो गया है। उद्योग–धंधे दम तोड़ने लगे थे, खेती किसानी चरमराने लगी थी, यहाँ के नौजवान पढ़ लिख कर रोजगार के लिए परदेस की राह खोज रहे थे या अपराध के रास्ते पर निकल पड़े थे. आमजन भय, भूख और भ्रष्टाचार की बेबसी से जूझने को मजबूर सा था।

ऐसे माहौल में जबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है तबसे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। मुख्यमंत्री ने कमान सँभालते ही सबसे पहला काम अपराधियों को चुनौती देने का किया जिनके उत्पात के चलते उद्योग, व्यापार निस्तेज होकर प्रदेश से मुंह मोड़ने लगा था। प्रजा को पीड़ा दे रहे भ्रष्ट कर्मचारियों को सुधरने के लिए चेताया। आधारभूत ढांचे सड़क, बिजली, पानी को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया. अन्नदाता किसान को वादे के मुताबिक ऋणमोचन की राहत दी। उत्तर प्रदेश के वासियों में अपने राज्य के प्रति लगाव का भाव जगाने के लिए पहली बार सरकारी स्तर पर 'उत्तर प्रदेश दिवस' का आयोजन किया।

इसके माध्यम से योगी जी वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना को सामने लाये और प्रदेश के हर जिले की अपनी खास उद्यमशीलता को उभारा, जो धीरे–धीरे आत्मविश्वास खो रही थी। मसलन अलीगढ़ का ताला, मेरठ की कैंची, रामपुर का चाकू, कानपुर का कपड़ा और चमड़ा, फिरोजाबाद की काँच की कला, बनारस की साड़ी, मुरादाबाद का पीतल, लखनऊ की चिकनकारी, सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी, मथुरा का चांदी वर्क आदि इत्यादि। इतनी जमीनी तैयारी के बाद राजधानी लखनऊ में एक ऐसे व्यापार महाकुम्भ का आयोजन कर डाला जिसे निरंतर पिछड़ते जा रहे उत्तर प्रदेश के विकास की राह में लम्बी छलांग कहा जा रहा है।

गोमती के तट पर फरवरी के अंतिम सप्ताह में गुलाबी मौसम में आयोजित निवेशकों के इस शिखर सम्मेलन में देश भर के चोटी के व्यापारियों की आमद और उसमे व्यक्त किये। उनके वादों और इरादों पर गौर किया जाये तो ये कहा जा सकता है कि भविष्य उज्जवल है। उत्तर प्रदेश से ही सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस समिट में दिलचस्पी सोने में सुहागा साबित

हुई। यूँ तो सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य के साथ वो अपने राजधर्म के सफर पर निरंतर अग्रसर हैं। पर मोदी उत्तर प्रदेश को पूर्वी भारत ही नहीं पूरे देश के लिए विकास केंद्र के रूप में देखने की आशा करते हैं। उनका विश्वास है कि ये क्षमता उत्तर प्रदेश में है। वो अब भव्य और दिव्य न्यू यू.पी. के निर्माण की आशा रखते हैं। इस समिट में प्रधानमंत्री ने 20 हजार करोड़ रुपये निवेश वाले डिफेंस प्रोडक्शन कोरिडोर की पहली सरकारी सौगात भी उस बुंदेलखंड को दी, जो कृषि, व्यापार, रोजगार हर मामले में वर्षों से टूटा हुआ है।

प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने समिट के अगले दिन सार्वजनिक क्षेत्र की इस महत्वाकांक्षी डिफेन्स कोरिडोर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया की इसी साल मार्च के महीने से इस पर काम शुरू हो जायेगा। प्रदेश के झाँसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़ जिलों में ही नहीं, लखनऊ और कानपुर में भी इसे विस्तार दिया जायेगा। इन सभी जगहों पर रक्षा मंत्रालय की टीम भेजी जा रही है और 50 साल के लिए मास्टर प्लान बनाया जायेगा। आने वाले 50 साल में इस उद्योग की तकनीकी जरूरतों, बदलाव और क्षमता पर चर्चा शुरू हो गयी है। यही नहीं डिफेन्स प्रोडक्शन के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के साथ छोटी निजी औद्योगिक इकाइयों को भी जोड़ा जायेगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सौगात से बाग–बाग हैं और कहते हैं अभी तो 20 हजार करोड़ का यह निवेश शुरुआती है जो एक लाख करोड़ तक जायेगा। इस कोरिडोर के माध्यम से बहुत संभावनाएं हैं, बल्कि देश में जितनी संभावनाएं यहाँ हैं कहीं नहीं हैं। पर मुख्यमंत्री को इस बात का ध्यान होगा कि इस उद्योग में क्षेत्रीय नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले। इसके लिए जरूरी कौशल प्रशिक्षण अभी से क्षेत्रीय नौजवानों को दिये जाने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर केवल बुंदेलखंड के बारे में सोचा हो ऐसा नहीं है, बल्कि विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पूर्वांचल को भी उद्योगों से आच्छादित करने की बात कही। यही नहीं उन्होंने दुनिया भर से आये निवेशकों को यू. पी. की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक उद्यमिता से भी परिचित कराया। हर जिले का सालों से अपना एक खास उत्पाद रहा है और उसके विकास और मार्केटिंग की असीम संभावनाएं हैं। यू. पी. के विकास के सरोकार में उन्होंने खेती किसानी को संरक्षण का सवाल भी उठाया और कहा कि किसान के उत्पाद की बर्बादी को रोकने की दिशा में भी निवेशकों को आगे आना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पूर्ववर्ती बसपा और सपा की सरकारों में राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल था। ऐसे माहौल में सामान्य लोगों का जीवन असुरक्षित था। मध्यम वर्ग की आकांक्षा पूरी करने और उद्योगों के विकास की कल्पना करना ही संभव नहीं था। पर योगी सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाकर राज्य में नेगेटिविटी को पाजिटिविटी में बदल दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की ही बात करें तो प्रधानमंत्री के यू. पी. को स्वस्थ करने की आकांक्षा के अनुरूप रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपने विभाग का पिटारा खोल दिया। पिछड़े बुंदेलखंड में रोजगार के नजरिए से झाँसी में उन्होंने 300 एकड़

जितनी प्रतिस्पर्धा, उतना निवेश : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमन्त्री पूरे देश के विकास के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ ज्यादा ही संकल्पित नजर आते हैं तो उसकी वजह भी है, क्योंकि वो यहीं माता अन्नपूर्णा व विश्वनाथ के नगर वाराणसी से संसद की दहलीज तक पहुंचे हैं। देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुँचने से पहले जो वादे उन्होंने जनता से किये थे, उन्हें पूरा करने की नैतिक जिम्मेदारी का एहसास तो है पर लगता एक कार्यकाल छोटा पड़ रहा है। देश के सिस्टम को पटरी पर लाने और भारत की ब्रांडिंग करने में ही चार साल का समय चुटकियों में गुजर गया। उस पर यू पी का पिछला निजाम विकास की कथा अपने हिसाब से लिखने में ही मशगूल रहा। बीमार यू.पी. के सही इलाज का मौका उन्हें कहीं जाकर 2017 में उन्हें तब मिला, जब योगी आदित्यनाथ के रूप में एक कुशल मुख्यमंत्री ने सरकार की कमान संभाली।

योगी सरकार ने जब फौलादी इरादों के साथ 10 महीनों में अपराध के झाड़-झंखाड़ को साफ किया तब कहीं जाकर मोदी के इरादों को हकीकत के पंख लगने शुरू हो सके। तब कहीं जाकर प्रधानमंत्री ने यू.पी. के बारे में अपने विजन को जाहिर करते हुए कहा कि क्या उत्तर प्रदेश अपने सामर्थ्य के साथ पूरा न्याय कर पा रहा है। उनका कहना था यू.पी. में बहुत संभावनाएं हैं। संभावनाओं, नीतियों, नियोजन और प्रदर्शन के योग से ही तरक्की आती है। उन्होंने भरोसा जताया टीम योगी यू.पी. में सुपरहिट परफारमेंस के लिए तैयार है। यहाँ के नागरिक इसके लिए तैयार हैं। यहाँ का मानस बना हुआ है। अब जरूरत इस बात की है कि समिट में हुए समझौते जल्द से जल्द धरातल पर उतारे जाएँ जिससे लोगों को रोजगार मिले और भव्य और दिव्य न्यू यू.पी. का सपना साकार होता दिखाई देने लगे।

यू.पी. में मूल्य हैं, गुण हैं, लेकिन अब बदले समय में मूल्यवर्धन की भी ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ कार्य संस्कृति और कारोबारी संस्कृति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में यू.पी. की जो सामर्थ्य है, उसमे मूल्यवर्धन की जरूरत है। सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों में काम कर रहे लोगों की आय बढाने के लिए भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हमें सक्षमता और विशेषज्ञता को एक दूसरे से जोड़ने के बारे में भी सोचना होगा। प्रधानमंत्री ने गंगा, यमुना और घाघरा समेत तमाम नदियों से सरसब्ज खेती से जुडी बड़ी चुनौती का जिक्र किया और कहा कि खेत से लेकर बाजार तक पहुँचने में एक अनुमान के अनुसार 90 हजार से एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान फसल की बर्बादी से किसानों को होता है। उन्होंने बायो फ्यूल की संभावनाओं को भी प्रदेश और देश के हित में बताया।

उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने चुनौती पेश करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखा है। क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस बात की प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि दोनों में से पहले कौन एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बने। यू.पी. अन्य राज्यों से भी विकास के मामले में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये प्रतिस्पर्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही राज्य में निवेश बढेगा, राज्य का विकास होगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। राज्यों में इस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को और भी मजबूत करेगी।

जमीन पर नयी कोच फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया। साथ ही वर्तमान रायबरेली कोच फैक्ट्री की क्षमता तीन गुना बढ़ाने का वादा किया है। अभी रायबरेली में 500 से 600 कोच प्रति वर्ष बनाये जा रहे हैं। 2021 तक हर साल 3000 कोच बनाने की योजना है। फतेहपुर जिले में रेल पार्क और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का इको सिस्टम विकसित किया जायेगा, जिसमे रेल में काम आने वाले उपकरण तैयार करवाए जायेंगे। बुंदेलखंड से लगा फतेहपुर जिला विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा रहा है। इरादा है कि यू. पी. में आने वाली शताब्दी, राजधानी या अन्य गाड़ियों के फर्स्ट क्लास, ए सी के डिब्बे ही चमचमाते न दिखाई दें बल्कि गरीबों के लिए बने सामान्य डिब्बे भी चमचमाएं ताकि सुरक्षित और आरामदेह पर्यटन सबके लिए सहज सुलभ हो। पूर्वांचल में बहराईच से मैलानी के बीच दुधवा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट को जोड़ने वाली मीटर गेज लाइन को हेरिटेज लाइन में बदला जायेगा ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक लोको शेड स्थापित करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया।

व्यापार महाकुम्भ में निजी क्षेत्र के निवेश की बात करें तो फार्च्यून 500 में शामिल 120 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बकौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समिट की बदौलत 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपये के 1045 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। यह राशि यू. पी. के 2018–19 के सालाना बजट के बराबर है। योगी ने 'यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट' के **आयोजन की सफलता की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें 10 देशों, 110 कम्पनियों, 100 मीडिया हाउसेज और 600 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 32 सत्रों के दौरान लगभग 120 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। समिट में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 10 फोकस सेक्टर्स–एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल, एमएसएमई, आईटीआईटीईएस एण्ड स्टार्ट–अप, इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म, टूरिज्म, सिविल एविएशन और रिन्यूएबिल एनर्जी आदि के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा हुई। साथ ही, डिफेन्स और एयरोस्पेस पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।**

एक बीमार राज्य की सेहत सुधारने के लिए जिन पूंजीपतियों ने यहाँ निवेश का वचन दिया है उनमे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अम्बानी हैं जो टेलिकॉम सेक्टर में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करना चाहते हैं। अदानी समूह के गौतम अदानी राज्य में कृषि क्षेत्र में भण्डारण और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगले पांच सालों में 35 हजार करोड़ रुपये लगाने का इरादा जाहिर करके गए हैं। आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला अपने परंपरागत व्यवसाय में 25 हजार करोड़ रुपये लगायेंगे। महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहनों की फैक्ट्री लगाने का ऐलान करके गए हैं। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन यू. पी. में टी.सी.एस. का नया कैम्पस

परिवेश से निवेश आया : योगी

उत्तर प्रदेश की बागडोर सँभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया था कि उनकी प्राथमिकतायें क्या होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास की साधना। इसके लिए सबसे जरूरी था भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। बुरी आदतें देर से जाती हैं पर मोदी की तरह राग-द्वेष से परे योगी ने पुलिस प्रशासन ईमानदार हाथों में सौंपकर पहले ये सुनिश्चित किया कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या सुधर जाएँ। समय तो लगा पर नतीजे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। यही वजह है कि समिट में योगी निवेशकों को यह भरोसा दिलाने के लायक थे कि यू.पी. में परमात्मा और प्रकृति की कृपा है। सुरक्षा के लिहाज से आज उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश है। वो ये बताना चाह रहे थे कि पहले उद्यमी असुरक्षा की वजह से नहीं आते थे पर आज निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सर्वथा उपयुक्त है।

दूसरी कठिनाई थी फाइलों की सुस्त चाल की। योगी ने इस मसले को कड़ी के साथ सुलझाते हुए एक ओर तो ढीले अफसरों को सन्देश दे दिया कि सुधर जाओ वर्ना काम करना सिखा दिया जायेगा। दूसरी ओर प्रदेश के हित की योजनायें फाइलों के मकडजाल में न फंसें, इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरलेंस प्रणाली शुरू कर दी। योगी सरकार की एक और कोशिश काबिलेगौर ये रही कि उन्होंने प्रदेश में सामान रूप से सभी जगह विकास पर ध्यान केन्द्रित किया। इसके लिए उन्होंने हर साल जाड़ों में होने वाले लखनऊ महोत्सव के बजाय 24 जनवरी को 'उत्तर प्रदेश दिवस महोत्सव' का आयोजन किया और इसे महज मनोरंजन के आयोजन से लघु और मध्यम उद्यमियों की कारीगरी की प्रदर्शनी में बदल दिया। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नया फलसफा दिया। ताकि यू.पी. हर जिले के खास हुनर को उभारा जा सके, एम. एस.एम.इ. के जरिये उन्हें हर प्रकार की सहूलियत दिलाई जा सके और उनके उत्पाद को बाजार तक लाने में सहयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री एक योगी हैं पर उन्होंने दिखा दिया है की वो प्रजा के हित में कैसी भी कठिन साधना कर सकते हैं और प्रदेश को माडर्न लुक देने में सक्षम हैं।

और वाराणसी में एक आई.टी. केंद्र खोलेंगे। एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा मनोरंजन के क्षेत्र में 18 हजार 750 करोड़ रुपये लगाने की बात कह कर गए हैं। ये तो कुछ बड़े निवेशकों जिक्र भर यहाँ है और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ उतरकर पूँजी लगाने की बात इस समिट में की गयी। मुख्यमंत्री ने समिट में भाग लेने आई पार्टनर कण्ट्रीज–जापान, थाईलैण्ड, नीदरलैण्ड, फिनलैण्ड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और मारिशस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन देशों द्वारा निवेश करने से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

इन्वेस्टर्स समिट के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी योगी सरकार के कामकाज पर गदगद नजर आये और बोले यू पी में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। देश की सबसे बड़ी श्रमशक्ति और सबसे ज्यादा उपभोक्ता इस प्रदेश के पास हैं और इसी वजह से निवेशकों ने यहाँ पूँजी लगाने का उत्साह दिखाया है। यू. पी. के विकास से ही भारत के विकास को पूर्णता मिलेगी। जी.एस.डी. पी. के आकार के हिसाब से यू.पी. देश में चौथी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। राज्य सरकार ने बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2017 को लागू करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो प्रणाली और आर्थिक सुरक्षा के बारे में जो उपाय किये हैं, उससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक सम्पदा–विशेषकर जल संसाधन, देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति और विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण देश के अन्य क्षेत्रों से अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यहां के युवा पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती को अपने जन्म और व्यक्तित्व निर्माण की धरती बताते हुए उन्होंने कहा कि चेतना और प्रतिभा का आर्थिक विकास के लिए प्रभावी उपयोग करने का लक्ष्य हमारे सामने है। इस राज्य की आर्थिक क्षमताओं का समुचित उपयोग करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के विकास से ही भारत के विकास को पूर्णता मिलेगी। यह समिट उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्र सरकार की पहल पर राज्यों को मिलने वाली धनराशि बढ़ी है। साथ ही, राज्यों की जिम्मेदारियां भी। इस बदलाव में केन्द्र व राज्य सरकारों ने परस्पर सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि समिट का आयोजन किया जाना एक बात है, लेकिन उसका सफल आयोजन होना अलग बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को शक्ति मिली है और उत्तर प्रदेश को भी मजबूती मिली है।

राष्ट्रपति ने कहा कि शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था, तार्किक टैक्स–व्यवस्था, उद्यम चलाने में सहायक माहौल, सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, यातायात की सुविधा आदि सभी क्षेत्रों में केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रियता से भी

निवेशकों में उत्साह बढ़ रहा है। इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए गए हैं। तीन इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का निर्माण करके, उन्हें 'ईस्टर्न फ्रेट कारिडोर' से जोड़ा जाना है। दो स्थानों पर 'नेशनल इन्वेस्टमेण्ट एण्ड मैन्युफैक्चरिंग जोन' की भी स्थापना की जा रही है। अनेक स्पेशल इकोनामिक जोन भी स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के अवसर हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि कई निवेशकों ने इन क्षेत्रों में उत्साह दिखाया है। उन्होंने कहा कि 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना से उत्तर प्रदेश में शिल्पकारों की आर्थिक प्रगति होगी और हर जनपद अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि जीएसटी तथा डिजिटल पेमेण्ट आर्थिक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम है। आर्थिक सुधारों के चलते पिछले 3 वर्षों में एफडीआई में बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। मारिशस की इस समिट में भागीदारी से राज्य और भारत को लाभ होगा। मारिशस और भारत का पुराना सम्बन्ध रहा है। हल्दिया से इलाहाबाद तक इनलैण्ड वाटरवेज, हवाई परिवहन, सड़क निर्माण, ऊर्जा उपलब्धता तथा मेट्रो रेल आदि की चर्चा करते हुए कहा कि इन सभी से राज्य अग्रसर होगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों और प्राविधानों की सराहना करते हुए कहा कि इनसे दूरगामी लाभ होंगे। उन्होंने कहा कि नवयुवकों को कौशल विकास से जोड़कर उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। यहां पर कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म की भी पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समिट के सफल आयोजन से युवाओं और किसानों को विकास के अवसर मिलेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास से पूरे देश के विकास को महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी माना कि यह समिट परिवर्तन की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। सरकारों के बदलने से किसी प्रान्त की स्थिति में भी परिवर्तन हो, यह जरूरी नहीं लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्य की स्थिति में बदलाव लाने का इतिहास रचा है और यहां से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। आज के समय में निवेशक के सामने यह विकल्प होता है कि वह निवेश को किस प्रान्त व किस देश में करे। निवेशकों को आकर्षित कर विकास की धारा को दिशा दी जा सकती है। निवेश से आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है और फिर राजस्व बढ़ता है। राजस्व बढ़ने से सरकार के संसाधन बढ़ते हैं। इन संसाधनों के बढ़ने से गरीबों की सेवा करने में मदद मिलती है। सोशल व फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोत्तरी होती है। इन सबसे आकर्षित होकर निवेशक और पूंजी निवेश करता है और फिर यह विकास का चक्र चलता रहता है।

सुरक्षा में भी रोजगार के अवसर : राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी सरकार को सजग करते हुए सुझाव दिया कि साइबर सिक्यूरिटी के लिए अलग से प्लान तैयार करना चाहिए। अब जबकि प्रदेश औद्योगिकीकरण की राह पर चल पड़ा है तो इंडस्ट्रियल साइबर सिक्यूरिटी मजबूत करना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह अपराध सबसे बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में निवेशकों के आने की अपार संभावनाएं जताते हुए राजनाथ सिंह ने उद्योगों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्यूरिटी की भी वकालत की। कानून और व्यवस्था की बहाली पर योगी सरकार की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा की सुरक्षा के क्षेत्र में दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक रोजगार देने की क्षमता है। प्राइवेट सिक्यूरिटी भी निवेश का एक बड़ा क्षेत्र है। राजधानी लखनऊ से सांसद के रूप में राजनाथ सिंह यहाँ के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर सदैव सजग रहे हैं।

श्री जेटली ने मुख्यमंत्री जी की निर्णय लेने की क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि आज 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' की आवश्यकताएं राज्य में पूरी हो रही हैं, जिनसे निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन पिछले 11 महीनों के दौरान अच्छे ढंग से स्थापित हुआ है। साथ ही, अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आया है. विकास के लिए परिवहन और रेलवे नेटवर्क जरूरी हैं। इनकी राज्य में उपलब्धता है। बड़ी संख्या में हाईवेज हैं। सांस्कृतिक व धार्मिक पर्यटन विकास की सम्भावनाएं हैं। केन्द्र

आवागमन सुगम बनायेंगे : नितिन गडकरी

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को रोडमैन कहा जाता है और उद्योग व्यापार के विकास के लिए अच्छी सड़क का महत्त्व होता है, इस बात से कौन इंकार कर सकता है। टीम योगी की डगर को आसान बनाने के लिए गडकरी ने यू.पी. में दो लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का जाल बिछाने का वादा किया है. यही नहीं जलमार्ग परिवहन को भी विकसित करने का काम चल रहा है। अब तक पटना से वाराणसी तक क्रूज चलाकर पर्यटन का काम चल रहा था, अब इसे बढाकर इलाहाबाद तक कर दिया गया है। साथ ही गंगा के किनारे पर्यटन को विकसित करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। उनका मानना है कि यू.पी. में पैसे की कमी नहीं है और न ही पावर की। कमी है तो बस विजन की। यह ऐसा राज्य है जो खुद तो धनवान है जनता गरीब है। अब योगी सरकार ने प्रदेश में विकास का बीड़ा उठाया है जिसमे केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है।

और राज्य के सहयोग से ग्रामीण व शहरी अवस्थापना सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी। गांवों में सड़क, आवास, बिजली और शौचालय की उपलब्धता होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलेगी।

राज्यपाल राम नाईक ने समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है, जिसकी सफलता विकास के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम एवं जनता को बधाई दी। जब राज्य के युवा को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे, तो वह दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करेगा। यह एक नया परिवर्तन है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। राज्य में भरपूर मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जिन्हें नई दिशा देकर और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। योजनाएं बनती तो हैं लेकिन समय पर पूरी नहीं हो पाती, जिससे समय के साथ–साथ लागत भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समिट के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश अधिक गति से आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती उनकी जन्म भूमि और कर्म भूमि रही है। आज जब भी विकास की बात की जाती है, तो उसमें यह देखना होता है कि वंचितों, किसानों और महिलाओं को विकास की इस यात्रा में कैसे भागीदार बनाया जाए। वर्तमान सरकार के 11 महीनों के कार्यकाल में प्रदेश के विकास का रोडमैप किस प्रकार का हो और प्रत्येक व्यक्ति को विकास का लाभ कैसे पहुंचे, इसका समाधान किए जाने में सरकार सफल हुई है। 'यू.पी. दिवस' के अवसर पर 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना का लागू किया जाना इन्वेस्टर्स समिट की पहली कड़ी थी। इस योजना से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही मुद्रा योजना, स्टार्टअप इण्डिया, स्टैण्डअप इण्डिया और मेक इन इण्डिया योजनाओं को जोड़ते हुए लागू किया जाएगा।

उद्यमियों और उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रोत्साहन ही नहीं, बल्कि ढांचागत बदलाव और प्रक्रिया के सरलीकरण के माध्यम से सहूलियतें उपलब्ध करायी जा रही हैं। व्यापारिक उत्पादों की उपभोक्ता तक लास्ट माईल कनेक्टिविटी की कामयाबी के लिए आधारभूत संरचना का होना बहुत जरूरी है। मसलन सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, लोजिस्टिक्स यानी परिवहन, ढुलाई और सबसे ऊपर कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था भी ऐसी जो अपराधियों, गलत काम करने वालों में भय पैदा करे। यू. पी. आवागमन को नया सुगम लुक देने के लिए बड़े शहरों में मेट्रो रेल के विकास में भी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इस बारे में योगी कहते हैं की लखनऊ में तो मेट्रो रेल का काम चल ही रहा है। कानपुर, मेरठ, आगरा में मेट्रो रेल की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर और झाँसी में भी मेट्रो रेल लाइन बनेगी। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कुशलता के साथ मेजबानी का दायित्व निभाया। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मारिशस के पूर्व राष्ट्रपति तथा वर्तमान में मार्गदर्शक मंत्री, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं डा. दिनेश शर्मा, केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, बड़ी संख्या में निवेशक व उद्यमी, शासन–प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

किसी ने कहा है कि सही परिवेश दीजिये निवेश अपने आप चला आएगा। अपराध की भूमि पर व्यापार नहीं पनप सकता। व्यापार नहीं पनपेगा तो न रोजगार के रास्ते खुल पाएंगे न सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सरकार को राजस्व मिल पायेगा। **इसे भयमुक्त प्रशासन की बहाली ही कहा जायेगा जब वो टाटा संस जो लखनऊ से टी सी एस बाहर ले जाने की बात कह रहे थे अब कहते हैं कहीं नहीं जायेगा बल्कि एक इकाई बनारस में भी खोलेंगे।** ज्ञात हो की प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में भी ऐसा ही भयमुक्त माहौल बनाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज गुजरात के विकास की कुंडली सबके सामने है। तब में और अब में एक सकारात्मक बात ये है कि गुजरात को केंद्र से भरपूर सहयोग की अपेक्षा नहीं हुआ करती थी। आज यू. पी. की बीमारी के इलाज के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलकर साथ खड़ी है। समिट के दो दिनों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह समेत डेढ़ दर्जन केंद्रीय मंत्रियों की भागीदारी इस बात का सबूत है की उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र और राज्य डबल इंजन की तरह काम करने को तैयार हैं।

भविष्य के उद्योगों पर नजर : सुरेश प्रभु

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सुरेश प्रभु ने बताया की उनका मंत्रालय ऐसे उद्योगों पर फोकस कर रहा है, जिनमे भविष्य में प्रचुर संभावनाए हैं। उन्हें योगी सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना में काफी दम नजर आया। भौगोलिक और क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाई इस योजना को अगर गंभीरता से लागू किया गया तो इसके उत्साहवर्धक परिणाम मिलेंगे। रोजगार के साथ यह स्वरोजगार को बढ़ावा देगी।

कपड़ा यू.पी. का ग्रोथ इंजन : स्मृति ईरानी

केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कपडा उद्योग के उत्तर प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। टेक्सटाइल क्षेत्र में 7 हजार करोड़ रुपये के शुभ संकेत मानते हुए उन्होंने कहा की कॉटन के साथ जूट उद्योग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सौर ऊर्जा का सहारा लिया जा सकता है। उन्होंने कानपुर की बंद मिलों और होजरी उद्योग की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मंत्रियों सतीश महाना और सत्यदेव पचौरी को सौंपी.

ऐसा मौका बार–बार शायद मिले न मिले। इस शिखर सम्मेलन के नतीजों से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया की 4 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव और मिले हैं। इनमे मारीशस, चेक गणराज्य, थाईलैंड समेत अन्य कई देशों के प्रस्ताव भी शामिल है। पर यह अच्छी बात है कि वो सतर्क हैं। इनमे से कोई बैंक डिफाल्टर न हो, सस्ती जमीन हासिल करने वाला कोई जालसाज न हो, सही व्यापारी को रिश्वत या लालफीताशाही का पहले की तरह शिकार न बनना पड़े इसके लिए उन्होंने कहा है की प्रत्येक निवेश प्रस्ताव की मोनिटरिंग वो स्वयं करेंगे। साथ ही इन प्रस्तावों से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को बंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बम्बई जैसे शहरों की धूल न फांकनी पड़े, उन्हें लखनऊ, कानपुर, नोएडा, आगरा मेरठ आदि शहरों में ही रोजगार मुहैय्या हो तो क्या कहने। मुख्यमंत्री को आशा है कि उनकी सरकार तीन सालों में चालीस लाख रोजगार पैदा करने जा रही है। संतोष की बात ये है की राज्य का मुखिया संवेदनशील, सजग और सतर्क है। तो फिर उत्तर प्रदेश के विकास की राह में ये इन्वेस्टर्स समिट एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। याद रहे कि अभी औद्योगिक विकास के पैमाने पर देश में उत्तर प्रदेश टॉप टेन राज्यों की सूची से बाहर है और ग्यारहवें से बीसवें स्थान के बीच कहीं झूल रहा है।

गाँवों में हाई स्पीड नेट : मनोज सिन्हा

केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि इस साल दिसंबर के अंत तक सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इन्टरनेट सुविधा मिल जाएगी। प्रदेश की कुल 55,470 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में 25,920 ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इन्टरनेट की सुविधा मिल चुकी है। बाकी में इसी साल के अंत काम पूरा कर लिया जायेगा। मनोज सिन्हा और उप मुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में समिट में 55 हजार करोड़ रुपये के निवेश हुए हैं।

दुनिया पैसा लगाने को तैयार : हरसिमरत कौर बादल

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हरसिमरत कौर का कहना था की पूरी दुनिया इस क्षेत्र में हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहती है। पिछले साल दिल्ली में वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में 60 से अधिक देशों का आना और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलना इस बात का सबूत है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी आई.टी.सी., गुजरात मिल्क को-आपरेटिव, पतंजलि फूड पार्क के प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की.

पर्यावरण की आसान एन.ओ.सी. : महेश शर्मा

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डाक्टर महेश शर्मा ने कहा की उद्योगों के लिए पर्यावरण की नो ओब्जेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा। ई वेस्ट कलेक्शन को भी उद्योग का दर्जा मिलेगा। ई वेस्ट एकत्र करने के लिए अभी देश में 30 प्लांट लगे हैं। अब नोएडा में भी एक प्लांट लगने जा रहा है। जो प्लांट में ई वेस्ट लायेंगे उन्हें इंसेंटिव दिया जायेगा। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है पर्यावरण को संतुलित रखते हुए उद्योगों के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

योगी ने साहसिक काम किया : पीयूष गोयल

पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा जाने से भी डरते थे। डर था कि नोएडा जाने से उनकी कुर्सी चली जाएगी। जबकि नोएडा ऐसा स्थान है जहाँ सबसे ज्यादा रोजगार हैं। मुख्यमंत्री न केवल वहां गए बल्कि लगातार जा रहे हैं। योगी ने ये बेहद साहसिक काम किया है। उन्होंने बताया की अगले साल कुम्भ के लिए इलाहाबाद के आस-पास पांच स्टेशनों को अपग्रेड किया जायेगा। कोहरे से निपटने के लिए अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली रेलवे में लगाई जाएगी ताकि यात्रियों को ट्रेनों के लेट या रद्द होने के कष्ट से बचाया जा सके।

यू.पी. में मौलिक परिवर्तन आया : अरूण जेटली

योगी सरकार के ग्यारह महीने के कामकाज की सराहना करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे और कहा की योगी में कड़े, कड़वे और कठिन फैसले लेने की क्षमता है। ये शिखर सम्मेलन यू.पी. के एजेंडा को बदलने का प्रयास है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की क्षमता भी निवेशकों को मुख्यमंत्री में दिख रही है। योगी सरकार ने दिखा दिया है की यू.पी. में कानून व्यवस्था स्थापित हो सकती है। यह मौलिक परिवर्तन आया है।

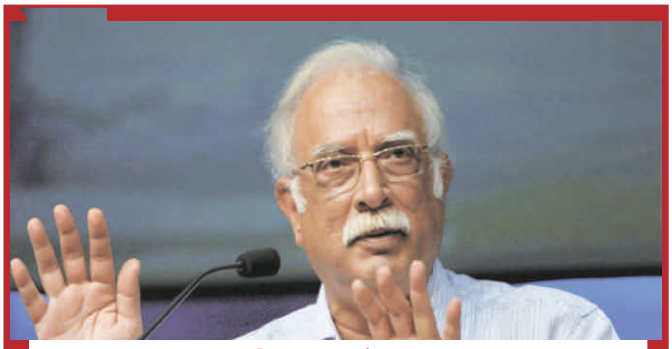

जेवर एयरपोर्ट 24 में तैयार हो जाएगा : राजू

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि वर्ष 2024 में यू.पी. के जेवर एअरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जायेंगी। उन्होंने बताया की प्रदेश में एयर पैसेंजर में 28.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और यहाँ एविएशन बेस को मजबूत करने की जरूरत है। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया की ग्रेटर नोएडा में बनने वाला जेवर एअरपोर्ट एविएशन इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किया जायेगा, यहाँ पर मेंटिनेंस, रिपेयर, ओवरहौल का काम किया जायेगा। उन्होंने निवेशकों से कहा घाटा हमारा होगा मुनाफा आपका होगा।

अब माहौल बदला : निर्मला सीतारमण

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहन नहीं होने से पिछले 20-25 साल कोई काम नहीं हुआ है। अब माहौल बदला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में काम हो रहे हैं। अगले पांच साल का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं।

अब यू.पी. सुरक्षित : जनरल वी.के. सिंह

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह का मानना था की यू.पी. पहले इतना सुरक्षित कभी नहीं था। उन्होंने कहा की उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश है। जैसे रवांडा और चीन में कुछ घंटों या दिनों में कारोबार की प्रक्रिया पूरी हो जाति है, उसी तरह का माहौल अब यू.पी. में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिये मिलेगा।

रोजगार मिले तो कौन घर से दूर जाये : राम नाइक

राज्यपाल ने कहा कि मानव संसाधन के मामले में यू.पी. समृद्ध है। यहाँ हर साल 20 लाख ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं। यह भी एक निवेश है जो यहाँ मौजूद है। जब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा तो कौन मुंबई की झुग्गियों में जाना पसंद करेगा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का साथ देने के लिए 47 मंत्री, विधायक और अफसर सभी मिलकर काम करें तो उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढेगा। समय पर काम पूरा होगा तो परियोजना की लागत भी नहीं बढ़ेगी।

हमारी पर्यटन नीति सबसे अच्छी : केशव प्रसाद मौर्या

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि प्रदेश की विविधताओं और संपन्न परम्पराओं के कारण यू.पी. में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ की पर्यटन नीति देश में सबसे बेहतर है। यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमे न्यूनतम निवेश पर अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है।

लखनऊ को आई.टी. हब बनायेंगे : डॉ. दिनेश शर्मा

उप मुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा ने बताया की प्रदेश सरकार लखनऊ को आई.टी. हब बनाने जा रही है। इसके लिए नादरगंज में 40 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गयी है। इसमें आई.टी. पार्क, स्टेट डाटा सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सिलेंस, इनोवेशन सेंटर, मेंतार्स के लिए गेस्ट हाउस बनाया जायेगा।

भाईचारे का माहौल : सी.आर. चौधरी

केन्द्रीय वाणिज्य व उद्यमिता राज्य मंत्री सी.आर. चौधरी ने कहा लेदर उद्योग में भारत चीन से मुकाबला कर सकता है। कानपुर और उन्नाव के बीच लेदर पार्क के अलावा आगरा और एन.सी.आर. में भी लेदर पार्क की जरूरत का सवाल उठाया गया है, जिस पर विचार किया जायेगा।

बीमारू नहीं रहेंगे : रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीमारू राज्यों में बिहार और यू.पी. दोनों हैं। दोनों ही राज्य इस धब्बे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आई.टी. वो माध्यम है जिससे देश बदल रहा है। डिजिटल क्रांति में भारत पीछे नहीं रहना चाहता है और इसे सिंगापुर की तरह विकसित किया जाएगा। नोएडा व ग्रेटर नोएडा में इसकी अपार संभावनाएं हैं।

निवेशकर्ता बोले

यू पी की सेवा देशभक्ति

- मुकेश अम्बानी

देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अम्बानी देशभक्ति को अपना कर्तव्य मानते हुए यू.पी. में कदम रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। उनका वादा है कि 2018 तक प्रदेश के हर गाँव तक जिओ नेटवर्क का ऐसा जाल बिछा देंगे जो राजधानी से सीधे गाँव की पंचायत को प्रशासनिक दृष्टि से जोड़ने में सक्षम हो। उनका दृढ़ विश्वास है कि यहाँ की 22 करोड़ की आबादी का उत्थान किये बिना भारत अपनी पूर्ण क्षमता के साथ विकास नहीं कर सकता। यू.पी. अगर पूरी ताकत से दौड़ने लगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को आर्थिक विश्व शक्ति बनने से नहीं रोक सकती। अम्बानी ने बताया कि जिओ नेटवर्क अब तक प्रदेश में 40 हजार रोजगार पैदा कर चुका है। अगले दो महीनों में जिओ यू.पी. में दो करोड़ मोबाइल फोन उपलबध कराएगा। रिलायंस टेलिकॉम, रिटेल, पोलिएस्टर, पेट्रोलियम के अपने कारोबारों से एक लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करने का बीड़ा उठाने को तैयार है। मुकेश प्रदेश के किसी विश्विद्यालय परिसर में चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र भी स्थापित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने गंगा को माता मानते हुए उसे स्वच्छ करने के 'नमामि गंगे' के प्रोजेक्ट में भी भक्तिभाव से हिस्सेदार बनने की पेशकश की है।

कृषि और ऊर्जा में सहयोग का इरादा

- अडानी

अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी का मानना है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए पहले कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। उनकी रुचि कृषि प्रधान प्रदेश में कच्चे माल व तैयार उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने और भण्डारण के कारोबार में है। इसके लिए वो लोजिस्टिक्स हब परियोजना में निवेश करना चाहते है। इस परियोजना के तहत ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर पोर्ट, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। राज्य में 40 परसेंट अनाज, फल, सब्जी हर साल भण्डारण का इन्तजाम न होने के कारण बर्बाद हो जाता है। किसानों की इस इस समस्या से निपटने के लिए अडानी समूह प्रदेश में छह लाख मीट्रिक टन अनाज भण्डारण क्षमता सृजित करेगा। भण्डारण के लिए जगह जगह बड़े गोदाम बनाये जायेंगे। वो प्रदेश में 1000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेंगे. 500 मेगावाट की सोलर सिटी बनायी जाएगी। वो सड़क और मेट्रो रेल परियोजनाओं में भी पैसा लगाने के इच्छुक हैं और विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय और कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी उनके एजेंडे में है। कुल मिलाकर अडानी यू.पी. के किसानों और नौजवानों की समस्याओं को हल करने में सरकार के मददगार बनना चाहते हैं।

पर्यटन पर फोकस

- आनंद महिन्द्रा

राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित आई.टी. कॉलेज में प्राचार्य रहीं माँ के बेटे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा यू.पी. को अपना ननिहाल मानते हैं। उनका मानना है कि यू.पी. में इतनी क्षमता है कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया की तरह अन्य राज्यों से नहीं दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। वो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का इरादा रखते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में वो क्लब महिंद्रा के माध्यम से पहले से राज्य में निवेश कर रहे हैं। आजकल विन्ध्य-वाराणसी सर्किट में 200 करोड़ रुपये से काम चालू है। मकसद ये है पर्यटन पर निकले सैलानियों के वास्ते घर से दूर घर जैसी सुविधाएँ हासिल हों। खुद को भी वो एक ऐसा मुसाफिर मानते हैं जो भटक कर घर आ गया हो।

नया उ.प्र. उभर रहा है

- सुभाष चन्द्रा

पिछली सरकारों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाकर योगी सरकार की कार्यशैली को सराहने वाले एस्सेल समूह के मुखिया सुभाष चंद्रा कहते हैं कि हमने पिछली सरकारों में 30 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन किये थे मगर काम 3 साल में केवल 3 हजार करोड़ का ही कर पाए। दो महीनों में हमने मुख्यमंत्री के साथ बैठकर जो काम किया उसके आधार पर कह सकता हूँ की एक नया उत्तर प्रदेश उभर रहा है।

यू.पी. को और देने की इच्छा

- कुमार मंगलम बिरला

ऊर्जा, आई.टी., अवस्थापना क्षेत्रों में बिरला समूह के अध्यक्ष कुमारमंगलम बिरला पांच सालों में 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश करना चाहते हैं। यूँ बिरला समूह आजादी के पहले से कई पीढ़ियों से अपनी तरह व्यापार और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में योगदान देता आया है।

माहौल दीजिये, निवेश लीजिए

- मनीष मोदी

मोदिको लिमिटेड के एम.डी. मनीष मोदी बोले 80 बरस पहले मेरे दादाजी ने मोदीनगर बसाया था। आज वहां ढाई लाख आबादी है, पर माहौल नहीं है। आप माहौल दीजिये हम निवेश करने और पसीना बहाने को तैयार हैं।

यू.पी. में कारोबार बढ़ाएंगे

- एन. चन्द्रशेखरन

उत्तर प्रदेश में टाटा संस टी.सी. एस. का नया कैम्पस बनाएगा और वाराणसी में एक आई.टी. केंद्र खोलेगा। साथ ही लखनऊ से अपने उद्यम को नहीं हटाएगा।

परदेसी मेहमान

मॉरिशस

मॉरिशस के पूर्व प्रधान-मंत्री और अब मार्गदर्शक मंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ बोले उत्तर प्रदेश से मॉरिशस का खून का रिश्ता है। इसी प्रदेश से 300 साल पहले उनके पूर्वज अंग्रेजी हुकूमत में एग्रीमेंट के आधार पर मॉरिशस गए थे और गिरमिटिया मजदूर कहलाये। एग्रीमेंट ही अपभ्रंश होकर गिरमिटिया बन गया। इसीलिए मॉरिशस को आज 'छोटा भारत' कहा जाता है। इन्वेस्टर्स समिट के बहाने उन्हें अपनों के बीच आकर बेहद खुशी हुई है। अब 'छोटा भारत' अपनी मूल जन्म भूमि उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार बनना चाहता है।

वाराणसी में यू.पी.-मॉरिशस प्रवासी भवन के लिए योगी सरकार से मिली दो एकड़ जमीन से प्रसन्न जगन्नाथ ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और मॉरिशस के संबंध काफी मधुर हो गए हैं।

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य की कई कंपनियां पहले से ही भारत में रक्षा क्षेत्र और हैवी व्हीकल इंजीनियरिंग में सहयोग कर रही हैं। अब पूर्वी यूरोप का ये देश कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करना चाहता है। वेलकम ग्रुप के सीनियर वी.के. प्रेसिडेंट रेडियम कोर, बोहेमिया बियर लिमिटेड के राकेश धवन और पेप्सेल की ओर से राम मेदिन ने भारतीय प्रतिनिधि वरिष्ठ आई.ए.एस. प्रभात कुमार के सामने उन क्षेत्रों में अपनी विशेषताओं का बखान किया।

थाईलैण्ड

समिट में पार्टनर कंट्री के बतौर शामिल थाईलैंड से आई डिप्टी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स सुतिमा कहती हैं भारत बुद्ध की धरती है। हमारे भगवान की तपस्थली से जुड़े सारनाथ, कुशी-नगर और श्रावस्ती उ.प्र. में ही हैं। इसलिए उ.प्र. हमारा दूसरा घर है। भारत के टाटा, बिरला और महिंद्रा ने थाईलैंड में निवेश किया है और चाहते हैं कि ईस्ट कॉमर्स कोरिडोर में भारत का निवेश और बढ़े। पर सुतिमा अपने प्रतिनिधि-मंडल के साथ भारत में निवेश के इरादे से आई थीं। उनका देश उ.प्र. के बौद्ध सर्किट में तो निवेश कर ही रहा है। इसके अलावा पर्यटन, हास्पिटैलिटी, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, आधारभूत ढाँचे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, कौशल विकास और लोजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी निवेश करना चाहता है। इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन से बात भी हुई।

निवेशकों का लाल कालीन पर स्वागत

राजधानी में निवेशक शिखर सम्मेलन के वास्तुकार रहे अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डा. अनूप चन्द्र पांडेय ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार निवेशकों को रेड कारपेट ट्रीटमेंट देने जा रही है। इसके लिये शासन से फील्ड स्तर तक की कार्ययोजना तैयार है। इसके लिये उद्योग बंधु की रीस्ट्रक्चरिंग पर विचार जारी है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े निवेशकों को शेयर बाजार से पूँजी की सुविधा दिलाने के लिये बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज और राज्य सरकार के बीच विस्तृत अनुबंध की तैयारी है। बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उद्योग बंधु के बीच बाकायदा एम.ओ.यू. साइन हो चुका है। अब विस्तृत एग्रीमेंट होना है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में छोटे मझोले की सूची बनायी जा रही है। इसके बाद इन उद्योगों से जुड़े निवेशक आई.पी.ओ. ला सकेंगे और शेयर मार्केट से पैसा उठा सकेंगे।

निवेशक अनुकूल वातावरण की जानकारी देते हुए डा. पांडेय बताते हैं कि सरकार ने निवेश में लालफीताशाही खत्म करने के लिये ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरिंग सिस्टम लागू कर दिया है। निवेशकों ने इस सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन शुरू भी कर दिया है। उद्योग बंधु में एक फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। इसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी तैनात किये जायेंगे। निवेशक यहां आने से पहले इसी सेंटर से संपर्क करेंगे। सेंटर से तत्काल एक अधिकारी निवेशक के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसके निवेश के संबंध में प्रदेश में उपलब्ध अवसर व सुविधाओं पर पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन की व्यवस्था होगी। साइट की विजिट करायी जाएगी। निवेशक किसी विभाग के अफसर से मिलना चाहेगा तो इंतजाम उसका भी रहेगा।

योगी सरकार के सपने को साकार करने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं डा पांडेय। वह कहते हैं निवेश के लिये पहली आवश्यकता जमीन की होती है। इसके लिये निवेशक चाहे तो खुद जमीन खरीद सकता है। वो चाहे तो यू.पी. एस.आई.डी.सी. से जमीन ले सकता है आवश्यकता पड़ने पर सरकार जमीन अधिग्रहण कराकर भी उपलब्ध करा सकती है। जमीन अधिग्रहण व अन्य कार्यों के लिये शासन के अनुभवी रिटायर्ड अधिकारियों को उद्योग बंधु से जोड़ा जायेगा।

उद्योग बंधु में एक टीम होगी जो निवेश के अछूते सेक्टर्स से निवेश लाने के रास्ते सुझाएगी। मसलन केन्द्र सरकार के तमाम पी.एस.यू. ऐसे हैं, जो बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। प्रदेश में अब तक इस पर फोकस नहीं किया गया। यह टीम सभी पी.एस.यू. उनके भावी निवेश व विस्तार योजनाओं पर निगाह रखेगी। अवसर सामने आते ही पत्राचार, संवाद, मुलाकात के माध्यम से उनके निवेश प्रोजेक्ट प्रदेश में लाने का जतन किया जाएगा। रेलवे, पेट्रोलियम, डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश के लिये बड़े अवसर लेकर आ रहे हैं।

हमारा इरादा फाइनेंस सेक्टर को भी यहां लाने का है। सेवा क्षेत्र में काम करने वाली तमाम कंपनियां अब तक प्रदेश से दूरी बनाये हुए हैं या बहुत छोटे स्तर पर उनकी भागीदारी है। फाइनेंस कंपनियों, प्राइवेट इक्विटी कंपनियों, वित्तीय परामर्श देने वाली कंपनियों को भी सरकार प्रदेश में निवेश के लिये बुलायेगी। इनके आने से निवेश के अवसर और बढ़ सकते हैं। इन्हें नोयडा, ग्रेटर नोयडा में जरूरी सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। समिट में जो एम.ओ.यू. हुए हैं, उनकी सूची बैंकों को दी जायेगी। ताकि बैंक खुद निवेशकों से संपर्क कर अपना ऋण आधार बढ़ा सकें। सरकार का इसमें सहयोग रहेगा।

अपराध पर नियंत्रण से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी

साभार :
बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिंदी संस्करण)

बात 3 फरवरी 2018 की है। इस दिन उत्तर प्रदेश में शामली जिले के झिंजिना गांव में एक मंदिर के पास स्थानीय पुलिस कमीज खड़े थे, जो रंगदारी वसूलने के लिए आ रहे किसी शख्स का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि उनके हाथ क्या आने वाला है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि किसी ने स्थानीय पंचायत के एक सदस्य से उसके परिजनों की जान बख्शने के बदले 1 करोड़ रुपये मांगे हैं। जब मोटर साइकल पर सवार दो लोग वसूली करने के लिए पहले से तय जगह पर पहुंचे तो पुलिस ने उनकी मुठभेड़ हो गई। देर तक गोलीबारी होती रही। जब गोलियों की आवाज बंद हुई तो पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। वहां गोलियों से जख्मी अकबर उर्फ मूसा पड़ा मिला। अकबर पड़ोस के गांव का रहने वाला था। उसके पास से कुछ नकदी, पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले। जख्मी अकबर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जब अकबर का कच्चा चिट्ठा खोला गया तो पता चला कि पुलिस को 13 से भी अधिक मामलों में उसकी तलाश थी। उस पर डकैती, आपराधिक षडयंत्र रचने, खतरनाक हथियार रखने जैसे कई संगीन आरोप थे। शामली के गांवों में अकबर का बहुत आतंक था, इसलिए उसके मरने की खबर सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता संभालने के बाद अकबर समेत 32 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को बताया है कि उनके सत्ता संभालने के बाद से राज्य में 1,000 से अधिक मुठभेड़ हो चुकी हैं। सिलसिला अभी चल ही रहा है। अपराधियों के खात्मे के साथ 2,500 से अधिक खूंखार अपराधी पकड़े गए हैं और 1,700 से अधिक अपराधियों के सिर पर पुलिस ने इनाम भी रखे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अक्सर दहशत में जीते हैं। लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में भी माहौल खौफनाक है क्योंकि वहां महिलाओं और लड़कियों के यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ की घटनाएं अखबारों में आती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश (जहां अकबर मारा गया था) रंगदारी, गोलीबारी और बलात्कार जैसे अपराधों के लिए कुख्यात रहा है। योगी सरकार को विरासत में मिले राज्य और जेलों पर नजर डालें तो जाहिर हो जाएगा कि सरकार ने अपराधियों के सफाये का मन क्यों बना लिया है। उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस की आनकानी से अपराधियों का लेखा–जोखा रखना कठिन होता है, वहां अपराध और जेलों की स्थिति और भी चौंकाने वाली है।

अपहरण के मामले

2008 से 2016 के बीच राज्य में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान अपहरण के मामले 193 प्रतिशत बढ़ गए थे, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थे। मायावती के शासनकाल में अपहरण 64 प्रतिशत और लूटपाट 51 प्रतिशत बढ़ी थी। हत्या

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आवास पर 'यू.पी. - 100 के वाहनों को झण्डी दिखाने के अवसर पर

के मामले भी उस दौरान राष्ट्रीय औसत से अधिक थे। अखिलेश के कार्यकाल के दौरान राज्य की महिलाओं की जान सांसत में रही। 2012 से 2016 के दौरान राज्य में बलात्कार की घटनाओं में 145 प्रतिशत तक तेजी आ गई। सामूहिक बलात्कार, जिसे गृह मंत्रालय अब अलग अपराध मानता है, की घटनाएं 19 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं। महिलाओं के शीलभंग के प्रयासों में तीन गुना से अधिक तेजी आई और यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी दोगुनी हो गईं। इस बीच अखिलेश सरकार के कार्यकाल में अपहरण के मामलों में 79 प्रतिशत से अधिक इजाफा हुआ। बच्चों के खिलाफ अपराध में भी राज्य पीछे नहीं रहा।

दलितों के साथ अपराध

राज्य में दलितों के साथ अपराध के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। देश में दलितों के साथ अपराध के हर चार मामलों में से एक उत्तर प्रदेश का ही था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए और इन्हीं इलाकों में पुलिस ने सबसे ज्यादा मुठभेड़ को अंजाम दिया। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में आपराधिक मामलों की दर भले ही ज्यादा है लेकिन अतीत में उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर कानून व्यवस्था का कोई असर नहीं दिखा है। पिछली सरकारें अपराधियों को बचाती थीं, जिससे जेल में बंद होने का डर उन्हें नहीं था। गृह मंत्रालय के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2008 से 2015 के बीच उत्तर प्रदेश में जेल जाने वाले हत्या के दोषियों की तादाद 120 प्रतिशत बढ़ गई, जबकि उसी दौरान देश भर में यह आंकड़ा केवल 15 प्रतिशत बढ़ा। बहुत अधिक हत्यारे इस दौरान जेल की सलाखों के पीछे गए फिर भी राज्य में हत्या के प्रयासों में 21 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो गई। जेल का डर भी हत्या के मामलों पर काबू नहीं कर सका और बाद की सरकार तो बलात्कार जैसे घृणित अपराध भी नहीं रोक सकी। राज्य की जेलों में बलात्कार की सजा पाने वालों की संख्या एक तिहाई बढ़ गई, लेकिन बलात्कार के मामले भी 145 प्रतिशत बढ़ गए। महिलाओं के यौन उत्पीडन के मामले भी उस दौरान तीन अंकों में बढ़ गए।

जेल का डर नहीं

अपराध की स्थिति गंभीर इसलिए भी हो रही है क्योंकि नए अपराधियों को जेल का डर नहीं सताता और जरायमपेशा पर उसका असर नहीं होता। जेल में बंद लगभग 7 प्रतिशत अपराधी एक से अधिक जेल गए हैं। देश भर में अपराधी दोबारा अपराध करने से कतरा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उलटी चाल चल रहा है। जेलों के भीतर भी अपरधियों के सुधरने की गुंजाइश नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश में जेल तोड़कर भागने की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं और फरार अपराधी मुश्किल से ही दोबारा पकड़े गए हैं। इसकी वजह यह है कि राज्य में बंदियों को जेल में सुधरने की सुविधाएं ही नहीं मिलतीं। देश भर में सबसे ज्यादा कैदी उत्तर प्रदेश की जेलों में ही हैं, लेकिन वहां सबसे कम कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है। राज्य की जेलों में 88,000 से अधिक अपराधी और विचाराधीन कैदी हैं, लेकिन उनमें से 1 प्रतिशत से भी कम को अपराध की दुनिया से दूर करने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने वाले कैदी जिस उद्यम से जुड़े हैं, उसमें उत्पादन बहुत कम होता है। 2015 में राज्य के कैदियों ने करीब 15 करोड़ रुपये तक का सामान तैयार किया जिसका प्रति व्यक्ति उत्पादन मूल्य करीब 1,700 रुपये है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की जेलों में कैदियों की संख्या उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, लेकिन वहां कैदियों ने क्रमशः रू 23 करोड़ और 48 करोड़ रुपये का सामान तैयार किया।

कारोबारी माहौल पर असर

अपराध के इस दुष्चक्र का असर प्रदेश के कारोबारी माहौल पर भी दिखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2012 और 2015 के बीच राज्य में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 39 प्रतिशत की कमी आई। राज्य में निवेश की गई पूंजी में बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन उस दौरान राज्य में उत्पादक पूंजी में 12 प्रतिशत की गिरावट आई। अपराधों में कमी किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और निवासियों पर कितना असर डालती है, इसका पता फिलीपींस से चलता है, जहां के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथियों में शामिल थे। फिलीपींस से मिली खबरें बताती हैं कि 2016 के बाद से वहां अपराध में 22 फीसदी कमी देखी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुमान के मुताबिक दुतेर्ते के सत्ता में आने के बाद से 3,000 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं, संदिग्ध नशाखोर भी शामिल हैं।

विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है, '2017 की पहली छमाही में फिलीपींस में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम के मुकाबले ज्यादा तेज वृद्धि हुई, लेकिन चीन से धीमी रही। जुलाई, 2016 में नई सरकार के काम संभालने के कुछ महीने के भीतर ही मजबूत वृद्धि देखी गई, जबकि 2017 की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था की शुरुआत धीमी थी।'

सख्त रवैया

उत्तर प्रदेश की आबादी, भौगोलिक विशेषताएं और अपराध की स्थिति फिलीपींस से अलग हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राज्य में अपराध कम हुए तो कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। निवेशक कानून व्यवस्था पर बहत नजर रखते हैं और हाल में निवेशक समेलन में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगाने का वायदा करने वालों के लिए कानून व्यवस्था अहम होगी। योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया है। राज्य के कुछ हिस्सों को वहां बाशिंदों के लिए नर्क बना चुके अपराधियों से प्रदेश को अस्थायी राहत मिल सकती है। लेकिन उनकी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा।

बजट यू.पी.

बुनियादी सुविधाओं से खुलेंगे विकास के द्वार

– प्रद्युम्न तिवारी

एक राज्य के राजा के पास यूं तो बहुत समृद्ध खजाना नहीं था, लेकिन जो भी था यह राज्य में कुछ इस तरह वितरित होता था कि जनता का एक धड़ा जहां सरकारी धन का भरपूर लाभ पा जाता था, वहीं दूसरी ओर आम जन का एक वर्ग इससे विमुख रहता था। इस स्थिति से राजा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। यह हालत देख राजा के एक दरबारी से उसे उचित सलाह दी। यह सलाह थी विकास व बराबरी की। चतुर राजा अपनी चिंता का हल पा चुका था। वह समझ गया था यदि विकास को साध लिया जाए तो बराबरी का लक्ष्य पाना भी आसान हो जाएगा। फिर क्या था, राजा ने विकास के मूल मंत्र को पकड़ा और राज्य की गाड़ी दौड़ा दी तरक्की के रास्ते पर।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास व बराबरी के इस मूल मंत्र को बखूबी पकड़ा और इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने वर्ष 2018–19 का कल्याणकारी बजट पेश कर दिया है। बजट से साफ है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गयी है। साथ ही जर (धन) का वितरण ऐसा रखा है जिससे वित्तीय अनुशासन की गाड़ी बेपटरी न होने पाए। विकास या यूं कहें उद्योग–धंधों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को लक्ष्य करते हुए इस काम के लिए बजट में भारी–भरकम धनराशि की व्यवस्था की गयी है। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि वित्तीय अनुशासन की सीमा नहीं लांधी गई। किसानों की कर्जमाफी जैसी किसी योजना के लिए धन की व्यवस्था नहीं की गयी है। पिछली बार के बजट में सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के लिए कुल 36,000 करोड़ रूपए रखे थे। पर इस बार किसानों को सीधा लाभ न देते हुए उर्वरक के अग्रिम भंडारण और कम ब्याज दर पर फसली कर्ज उपलब्ध कराने के लिए बजट में 200 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है। इस बार का बजट 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ रूपए का है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 21 हजार करोड़ रूपए अर्थात् 11.4 फीसदी अधिक है। वहीं राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का अनुपात 2.96 प्रतिशत होने से यह वित्त आयोग और एफआरडीएन मानकों के अनुरूप है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो धन रखा गया है, उससे निश्चित रूप से छोटे किसानों को फायदा होगा। सिंचाई को लेकर सरयू नहर

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत करने के लिए विधान सभा में जाते हुए

योजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना और बाण सागर परियोजना के जरिये पर्याप्त जल देकर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं। साथ ही डेयरी और कुक्कुट पालन के लिए 614 करोड़ रूपयों का प्राविधान किया गया है। किसानों से सीधी खरीद के लिए इस बार 5,500 नए केन्द्र खोलने का ऐलान भी सरकार की नेकनीयती को दर्शाता है।

जहां तक बुनियादी सुविधाएं मसलन बिजली और सड़क की बात है तो इनके लिए भी बड़ी रकम रखी गयी है। बिजली क्षेत्र के लिए 29,883 करोड़ रूपए रखे गए हैं। यह बीते साल की तुलना में 54 प्रतिशत ज्यादा है। इससे स्पष्ट होता है कि केन्द्र की मोदी सरकार की लोकसभा चुनाव से पहले हर घर में बिजली पहुँचाने की योजना के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार सजग है। अधिक बिजली से उद्योग–धंधों को भी बिना बाधा विद्युत आपूर्ति से निवेशक उत्तर प्रदेश का रूख आसानी से करेंगे। सड़कों, खासतौर पर एक्सप्रेस–वे के मामले में योगी सरकार का दृष्टिकोण बेहद सकारात्मक दिखायी देता है। बजट में चार एक्सप्रेस–वे (बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस–वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे, पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे और आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे) के लिए 2,700 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए स्टार्ट–अप और कौशल विकास पर खासा जोर दिया गया है। योगी सरकार तीर्थ स्थल पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके मद्देनजर कुछ धार्मिक सर्किट चुने गए हैं। साथ ही हर साल बरसाना की होली और अयोध्या में दीवाली मनाने के लिए भी धन की व्यवस्था की गयी है। नैमिषारण्य में जहां वैचारिक चिंतन होगा, वहीं काशी में देव दीपावली और लखनऊ महोत्सव के लिए ठीकठाक धन का प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक धरोहरों के लिए 110 करोड़ का प्राविधान है। अगले साल जनवरी में होने वाले कुंभ मेले के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रूपए इसलिए रखे हैं ताकि किसी को दिक्कत न उठानी पड़े। ब्रज तीर्थ के लिए 100 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की गयी है। सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड का भी विशेष ध्यान रखा है। बजट में सेहत व शिक्षा के प्रति भी योगी सरकार बेहद संवेदनशील नजर आयी। केन्द्र की महात्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भव को देखते हुए चिकित्सा का बजट 17.3 फीसदी बढ़ाया गया है।

उच्च, माध्यमिक, बेसिक और तकनीकी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 68,263 करोड़ की रकम की व्यवस्था की गयी है। लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा देने के लिए अहित्याबाई योजना में 21 करोड़ रूपए, मिड–डे मील के लिए 2,048 करोड़ रूपए, बेसिक स्कूलों में ही फल देने के लिए 167 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है। सरकार इस दिशा में भी सचेत दिखती है कि बच्चों को टाट–पट्टी पर बैठकर पढ़ाई न करनी पड़े, इसीलिए प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। यदि तकनीकी शिक्षा को स्टार्ट–अप और नवाचारों से जोड़कर देख जाए तो तकनीकी संस्थानों में रोजगार योग्य विद्यार्थी बड़ी संख्या में तैयार होंगे। इसी तरह मुसहर व बनटांगिया जाति के लिए योजना लागू करने से यह मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। मदरसों के आधुनिकीकरण, उर्दू–फारसी विद्यालय, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्ग के लिए प्रस्तावित योजनाओं से उन्नति की राह खुलेगी। अल्पसंख्यकों के लिए 3,862 करोड़ रूपए रखे गए हैं। आर्थिक विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि योगी सरकार के इस बजट में सभी क्षेत्रों के विकास की ईमानदार कोशिश की गयी है। इससे कृषि और रोजगार को भी बल मिलेगा। बजट में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण को तरजीह देकर गाँवों की तरक्की की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। एक जिला–एक उत्पाद योजना से प्रदेश में कलस्टर आधारित विकास में तेजी आएगी और निर्यात बढ़ेगा।

इस तरह कहा जा सकता है कि यह बजट विकास की बुनियाद मजबूत करने के साथ ही रोजगार के योग भी बनाएगा।

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तिलक हाल में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के सम्बन्ध में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए

सड़कों का विकास

- 11,343 करोड़ रूपए सड़क निर्माण के लिए।
- 1,817 करोड़ रूपए पुल निर्माण।
- 2,873 करोड़ रूपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
- 500 करोड़ रूपए मेट्रो परियोजनाओं के लिए (कानपुर-आगरा की डीपीआर तैयार। वारणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर व झाँसी में नयी नीति के अनुरूप प्रस्ताव)

शहरी विकास

- लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1,650 करोड़ रूपए।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारीडोर रीजनल रैपिड ट्राँजिट सिस्टम के लिए 250 करोड़ रूपए।
- लखनऊ सहित सभी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के विकास के लिए 300 करोड़ रूपए।
- मुख्यमंत्री शहरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 426 करोड़ रूपए।
- 1.5 करोड़ परिवारों को मार्च, 2019 तक बिजली कनेक्शन देना।
- 150 करोड़ सस्ती हवाई सेवा के लिए।

सेहत और शिक्षा

- गोरखपुर, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत सुपर स्पेशियलिटी और कानपुर तथा आगरा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 68,263 करोड़ रूपए।
- फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर के जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज बनाने के लिए 500 करोड़ रूपए।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पैरामेडिकल एवं नर्सिग कालेज बनेगा।
- पी.जी.आई. लखनऊ में 200 बेड बढ़ाने के साथ ही रोबेटिक सर्जरी भी शुरू की जाएगी।
- कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा में बर्न यूनिट के लिए 14 करोड़ रूपए।

बुंदेलखण्ड का विकास

- 1,005 करोड़ रूपयों से बुंदेलखण्ड के विकास को मिलेगी रफ्तार।
- 650 करोड़ रूपए बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए।
- 131 करोड़ रूपए सौर ऊर्जा वाले सिंचाई पंपों की स्थापना के लिए।
- 24 करोड़ रूपए से स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के तहत किसानों को सब्सिडी।
- 200 करोड़ रूपए विशेष परियोजनाओं के लिए।
- दुग्ध उत्पाद में देशी नस्ल पर जोर।
- 52 लाख रूपए नयी नंद बाबा पुरस्कार योजना के लिए।
- 75 करोड़ रूपए पं. दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के लिए।
- 15 करोड़ रूपए से डेयरी विकास फंड की स्थापना।
- 54 लाख रूपए गोकुल पुरस्कार योजना के लिए।
- बुंदेलखण्ड में गौवंश वन्य विहार और 5,000 तालाब बनेंगे।

सहकारिता विकास

- 200 करोड़ रूपए किसानों को कम ब्याज दर पर फसली कर्ज के लिए।
- 100 करोड़ रूपए उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण के लिए।
- 31 करोड़ रूपयों से होगा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण।

समाज कल्याण

- 7,858 करोड़ रूपए सामान्य एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास योजनाओं के लिए।
- 250 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए।
- 121 करोड़ अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए।
- 82 करोड़ रूपए सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए।
- 500 करोड़ रूपए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए।
- 100 करोड़ रूपए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं के लिए।
- 2,560 करोड़ रूपए 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के लोगों को वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के लिए।
- 1,706 करोड़ रूपए पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं के लिए।
- 200 करोड़ रूपए पिछड़ा वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए।
- 551 करोड़ रूपए पिछड़े वर्ग छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए।

प्रदेश का वार्षिक बजट (2018-19)

जो कोई नहीं कर पाया, वह कर दिखायेंगे

– योगीन्द्र द्विवेदी

पिछले विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार में कहते रहे थे कि यदि प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो विकास की गाड़ी में 'डबल इंजन' लग जाएंगे और प्रदेश केन्द्र सरकार से समन्वय कर ज्यादा तेजी से विकास करेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश के विकास की गाड़ी में भी 'डबल इंजन' लग गया है। पिछले वर्ष अपने पहले बजट में ही 'संकल्प–पत्र' में किसानों की एक लाख तक कर्ज माफी का वादा पूरा करते हुए इसके लिए 36,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था, जिसमें अधिकांश का आबंटन हो गया है। इससे मुक्ति पाने के बाद योगी सरकार ने हाल ही में पेश अपने दूसरे बजट में ज्यादा धन विकास के विभिन्न क्षेत्रों तथा संकल्प पत्र में किये वायदे पूरी करने की दिशा में आबंटित किया है। बजट में केन्द्रीय सहायता वाली परियोजनाओं के लिए आबंटन में भारी वृद्धि कर देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने का भी यथासंभव प्रयास किया गया है और इस तरह यह अगले वर्ष होने वाले लोकसभा आम चुनाव, यानी मिशन 2019 में विजय दिलाने की दिशा में भी अग्रसर है।

उदाहरण के लिए, 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' यानि मातृत्व लाभ के लिए 291 करोड़, 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के लिए 126 करोड़, 'स्वच्छ भारत अभियान' के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 करोड़ व शहरी क्षेत्रों में 1,100 करोड़, 'केन्द्रीय सड़क योजना' में 2,200 करोड़ तथा 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना' में 2,873 करोड़ का आबंटन किया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा को जमीन पर उतारने के भी प्रयास किये हैं कि वर्ष 2022 तक सभी भारतीयों के सिर पर छत हो। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 2,217 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 11,500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में सबको शिक्षित करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान पर 18,167 करोड़ तथा मध्यान्ह भोजन पर 2,048 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी ने ठीक ही कहा कि किसानों, नौजवानों, महिलाओं व गांवों को केन्द्र में रखकर समग्र विकास

का बजट बनाया गया है। इससे प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी। बजट में लोक निर्माण विभाग 22 फीसदी, बिजली व सिंचाई के बजट में 54 फीसदी बढ़ोतरी की गयी है। तीन लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट नौजवानों को रोजगार बढ़ाने वाला होगा। इसमें किसानों का भी ध्यान रखा गया है। लम्बित सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने से एक लाख हेक्टेयर सिंचित रकबा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यू.पी. का बजट पिछले वित्तीय वर्ष से 11.4 फीसद बढ़ा है, लेकिन सरकार ने जमीनी ढ़ांचे के विकास के लिए भी प्रावधान किये हैं। बिजली के बजट में 54 फीसद का इजाफा कर 29,883.05 करोड़ रुपये दिये गये हैं। लोक निर्माण विभाग को भी 22 फीसद बढ़ाकर 17,615 करोड़ रुपये दिये गये हैं। सिंचाई की लम्बित परियोजनाएं पूरा करने के लिए 10,938 करोड़ का प्रावधान है, यह तकरीबन 54 फीसद ज्यादा है। श्री योगी ने कहा कि कृषि को 8,403 करोड़, ग्राम्य विकास को 22,110 करोड़ का बजट दिया गया जो पिछले बजट से ज्यादा है। पंचायतीराज विभाग के बजट में 16 फीसद बढ़ाकर 17,222.55 करोड़ दिये गये हैं। चिकित्सा विभाग को 21,197.58 करोड़ रुपये ज्यादा दिये हैं। शिक्षा के सभी विभागों को मिलाकर 68,263 करोड़ दिया गया है। महिला एवं बाल विकास के बजट में 15 फीसदी बढ़ाकर 8814 करोड़ से ज्यादा दिया है। बजट में एससी–एसटी हितों पर विशेष जोर है। निश्चित रूप से ये कदम संतुलित विकास और 'सबका साथ, सबका विकास' की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा पेश 4,28,384 करोड़ का बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो पिछले बजट से 11.4 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि बजट में कोई नया कर या उपकर नहीं लगाया गया है और लगभग पांच हजार करोड़ का घाटा दिखाया गया है। बजट में औद्योगिक विकास के लिए भारी वृद्धि की गई है, जहां इस मद में पिछले वर्ष 20 करोड़ आबंटित थे, वहीं इस वर्ष नई परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ तथा पुरानी परियोजनाओं के विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का भारी आबंटन किया गया है। ढांचागत संरचनाओं जैसे सड़कों के लिए आबंटन उल्लेखनीय रूप से 22 प्रतिशत बढ़ाया गया है। ढांचागत परियोजनाओं के मामले में प्रदेश सरकार ने मेट्रो योजनाओं को महत्वपूर्ण माना है। लखनऊ मेट्रो को 216.97 करोड़ का आबंटन इसका प्रमाण है। योगी सरकार ने पूर्वांचल व बुंदेलखंड के विकास पर बहुत ध्यान दिया है, जिनकी अब तक उपेक्षा होती रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरुआती काम के लिए 650 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1,000 करोड़ का भारी आबंटन किया गया है तथा गोरखपुर को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 500 करोड़ का आबंटन किया गया है। इसके साथ ही आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए भी 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सदन को बताया कि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार का 2017–18 का पिछला बजट 3.84 लाख करोड़ रुपये का था। इस वर्ष का बजट 60 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। बजट में कुल प्राप्तियां 4 लाख 20 हजार 899.46 करोड़ रुपये दर्शायी गयी हैं। बजट में 7485.06 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, हालांकि लोक लेखा से इसकी पूर्ति किये जाने की उम्मीद की गयी है। बजट में निवेश, युवा कल्याण और राज्य में बुनियादी ढांचों के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। नयी योजनाओं के लिये बजट में 14341.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस बजट में समाज के उपेक्षित और गरीब लोगों पर भी ध्यान दिया गया है। उन्होने कहा कि ऐसे दूरस्थ गांव जो प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं और अभी तक उनका विकास नहीं हुआ है, उनके लिए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना लागू की जा रही है। इसी तरह अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने व पारम्परिक शिल्पों एवं लघु उद्यमों को संरक्षण देने के लिए 'एक जनपद, एक उत्पाद योजना' को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होने कहा कि बजट में किसानों के लिये कई योजनायें घोषित की गयी हैं। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के क्रियान्वयन के लिये 42 करोड़ 49 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। वित्तमंत्री ने प्रखर चिंतक दीन दयाल उपाध्याय का उल्लेख करते हुए कहा कि "मानव आजीविका के केवल तीन साधन हैं – कृषि, पशुधन और उद्योग। इन तीन साधनों के सहारे मानव अपने स्वावलम्बन से स्वाभिमानपूर्ण जीवन बिता सकता है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत विभिन्न सेक्टर्स में स्थापित होने वाले उद्योगों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017, यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति –2017, यूपी सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति –2017, यूपी इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017, यूपी एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017, वस्त्रोद्योग नीति–2017, फेरी नियमावली–2017 और यूपी खनन नीति–2017 लागू की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 फीसदी है। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.8 फीसदी अनुमानित है। वित्तमंत्री ने एक शेर से अपनी बात समाप्त की जो योगी आदित्यनाथ सरकार के इस बजट से जुड़े संकल्पों की अत्यंत मुखर अभिव्यक्ति है – "हमारा वादा है हर घर को जगमगाएंगे, दीयों की लौ को हवाओं से हम बचायेंगे। स्वर्ग उतरेगा एक रोज अपनी धरती पर, जो कोई कर नहीं पाया, वो कर दिखायेंगे।

किसानों की 'कर्जमाफी' पर पिछले बजट में भारी–भरकम राशि खर्च करने के बाद अब योगी सरकार ने कृषि योजनाओं के लिए 1010 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। योगी सरकार ने आलू किसानों की समस्याओं पर विशेष गौर

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तिलक हाल में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के सम्बन्ध में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए

किया है। आलू के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जहां रेल विभाग से दक्षिण भारत में आलू भेजने की व्यवस्था के संबंध में बातचीत चल रही है, वहीं वर्तमान बजट में बाजार हस्तक्षेप के लिए सरकार ने 50 लाख का आबंटन किया है। इसके अलावा किसानों को छुट्टा गौवंशों से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए बजट में 175.2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बुंदेलखंड में गोवंश वन्य विहारों के निर्माण के लिए 92.77 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उम्मीद करनी चाहिये कि इससे बुंदेलखंड में पशुओं को छुट्टा छोड़ने की 'अन्ना प्रथा' के कारण होने वाले नुकसान में कमी आयेगी। लघु डेरी योजना के लिए 74.70 करोड़ के आबंटन से छोटे पशुपालकों को विकास के अवसर मिलेंगे।

योगी सरकार ने प्रदेश में दशकों से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने तथा इनके माध्यम से किसानों व ग्रामीणों को लाभ दिलाने पर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए उसने सरयू नहर परियोजना को मूल योजना के अनुसार पूरी करने के लिए 1,614 करोड़ का भारी आबंटन किया है, जिससे किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 741 करोड़, मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1,701 करोड़ तथा कनहर सिंचाई परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसके साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए भी 1,004 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर भी ध्यान दिया है और इस दिशा में वह प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक अनेक कदम उठाने के संकेत बजट में दे रही है। 'जनसंघ' के संस्थापक और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय माडल के 125

स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके लिए 26 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इन स्कूलों में अंग्रेजी व गणित की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जायेगा। स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में एक दिन फल बांटने की विशेष व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए 167 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान पर 480 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिक्षा में व्याप्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों संबंधी विसंगतियां दूर करने के शानदार प्रयास हुए हैं, जिससे प्रदेश के छात्र अन्य प्रदेशों के छात्रों के साथ देश की मुख्य धारा में आ गये हैं।

प्रदेश की भाजपा सरकार बिजली क्षेत्र में उदय योजना के अंतर्गत तेजी से सुधार कर रही है और वह इस दिशा में कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचकती है। सभी जानते हैं कि पिछले वर्षों में लगभग आधी बिजली चोरी हो जाती थी, जिसे 'लाइन लास' बता दिया जाता था। लेकिन योगी सरकार ने सत्ता में आते ही बिजली चोरी रोकने के लिए कठोर कदम उठाये हैं। सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ का विशेष प्राविधान किया है। सरकार ने मार्च, 2019 तक सबको बिजली देने का लक्ष्य बनाया है और इसके लिए बजट में 1,880 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। कर्ज में डूबी बिजली कंपनियों के लिए उदय योजना में 4,891.72 करोड़ का प्राविधान किया गया है। उदय योजना पूरे देश में बिजली सुधार की दिशा में मोदी सरकार का नवीनतम कदम है, पर इसकी सफलता आने वाले समय में ही तय होगी। बिजली क्षेत्र में निवेश–ऋण के लिए 10,563.74 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए विशेष सम्मेलन भारी तैयारी के साथ करने जा रही है। इससे प्रदेश में भारी निवेश आने तथा युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की आशा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि प्रदेश के हर जिले में कोई न कोई खास चीज बनाई जाती है, जिसके उत्पादन में सुधार तथा बेहतर मार्केटिंग से इसकी बिक्री न केवल देश–प्रदेश, बल्कि विदेशों में भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने 'एक जनपद एक योजना' के लिए 250 करोड़ का आबंटन किया है। खादी एवं ग्रामोद्योग विकास के लिए 25 करोड़ अलग से रखे गये हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की अन्य खूबियां बताते हुए कहा कि प्रदेश में 14431.89 करोड़ की नई योजनाओं को चलाया जाएगा। तीन लाख युवाओं को प्रस्तावित नौकरियों में शिक्षा विभाग में 1.37 लाख, पुलिस में 1.62 लाख और अन्य विभागों में रिक्त पदों की भर्ती शामिल है। बजट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 250 करोड़, स्टार्टअप योजना के लिए 250 करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर 100 करोड़ का प्रावधान है। श्रमिकों, एससी–एसटी व अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के विवाह में मदद के लिए 478 करोड़ का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार नयी औद्योगिक नीति पर अमल करने के लिए 500 करोड़ के साथ ही बुलंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 650 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर लिंक परियोजना के लिए 550 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस परियोजना के लिए एक हजार करोड़ व आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के काम को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। युवाओ को रोजगार से जोड़ने के लिए 'एक जनपद एक उत्पाद' में 250 करोड़ का बजट रखा गया है। शिक्षकों के एक लाख 37 हजार व पुलिस विभाग के खाली पड़े एक लाख 62 हजार पदों पर भर्ती होगी। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में 291 करोड़ का बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की राह अपनाते हुए अपने दूसरे बजट में सबका साथ–सबका विकास की राह पकड़ी है। बजट में श्मशानों के रखरखाव व निर्माण के लिए तकरीबन 200 करोड़ का बजट रखा है, इस बजट से सभी तबके के अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण व अनुरक्षण किया जा सकेगा। इनमें 99 करोड़ रुपये ग्रामीण व 100 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए रखें गये हैं। अल्पसंख्यकों के विकास व कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओ में 2757 करोड़, अरबी–फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण पर 404 करोड़, अरबिया पाठशालाओं के अनुदान पर 486 करोड़ के साथ ही स्थायी मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 मदरसों के लिए 215 करोड़ का बजट दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वर्ष जनवरी में होने वाले कुम्भ 2019 के लिए 1500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बृज विकास परिषद के तहत आने वाले सभी सात स्थलों के लिए 100 करोड़, वाराणसी में केन्द्र के लिए 200 करोड़, गाजियाबाद में कैलाश–मानसरोवर भवन के लिए 94.26 करोड़, अयोध्या में योजनाओं के लिए 20 करोड़, टूरिज्म के लिए 70 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ताजमहल से लेकर फतेहपुर–सीकरी तक के विकास के लिए बजट में धनराशि दी गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'यह बजट वित्तीय अनुशासन के साथ ही महिलाओं, नौजवानों, किसानों और गांवों के विकास को समर्पित है। बजट समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।' उन्होंने अगले तीन साल में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया जिसे मीडिया की सुर्खियों में स्थान मिला। बेरोजगारी प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है और योगी सरकार की सफलता का इस मायने में आंकलन कुछ वर्ष बाद होगा। योगी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के रास्ते पर चलते हुए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी बजट में 2,757 करोड़ की भारी–भरकम व्यवस्था की है। निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से 'राजधर्म' का पालन किया है। प्रदेश में यह योगी सरकार का भले ही दूसरा बजट हो, पर इसके समुचित क्रियान्वयन का प्रदेश के विकास पर दूरगामी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के इस बजट का सबसे उचित आंकलन यही है कि यह पूरी तरह दूरगामी जमीनी विकास को समर्पित संतुलित बजट है।

उत्तर प्रदेश में

फिल्म निर्माण का खुला द्वार

– रजनीकांत वशिष्ठ

'फिल्म नीति' के ऐलान के समय सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री डॉ०नीलकंठ तिवारी, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश अवस्थी के साथ फिल्म निर्देशक एवं निर्माता

भारत में फिल्मों का मक्का भले ही बम्बई रहा हो पर यू.पी. की लोकेशंस, कथावस्तु बोली और कलाकार हर काल में बम्बई की फिल्मी दुनिया में छाए रहे हैं। रुपहले परदे पर यू.पी. के शहर लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूट, बरेली, मेरठ और झाँसी फिल्मों के टाइटल और गानों में जब तब झलकते दिखाई देते रहे हैं. पर चूंकि फिल्म निर्माण की तकनीकी बारीकियों का सारा तामझाम बम्बई में ही रहा। इसलिए यू.पी. के फिल्मी ब्रेन को अपना ठिकाना बॉलीवुड में ही खोजना पड़ता रहा है। पर जबसे महाराष्ट्र में यू.पी., बिहार के भैया को बाहर भगाओ आन्दोलन शुरू हुआ है तबसे उत्तर भारत के कलाकारों के सामने एक नयी चुनौती मुंह बाए खड़ी है कि वहां टिककर काम करें कैसे। ऐसे में इनवेस्टर्स समिट योगी सरकार ने ऐसी लोकल प्रतिभाओं के लिए यू.पी. में सम्पूर्ण फिल्म निर्माण की बुनियादी सुविधाओं का ढाँचा खड़ा करने के वास्ते निवेश का न्यौता देकर संभावनाओं के नए द्वार खोल दिये हैं। समिट के दौरान दो दिनों में ऐसे करीब 10 हजार करोड़ रुपये के सहमति–पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो अगर धरातल पर उतर आये तो बम्बई के ही टक्कर की फिल्मी दुनिया यू.पी. में बस सकती है और तब उत्तर भारत की हिंदी भाषी प्रतिभा को सामने बम्बई में नहीं भटकने की मजबूरी नहीं रह जायेगी।

यू.पी. की धरती पर फिल्म का सकल ढाँचा खड़ा करने वाले निवेशक के रूप में सामने आये उद्यमियों में एक नाम भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार और भाजपा नेता रविकिशन का है, जो 1,000 करोड़ रुपये की लागत से राजधानी लखनऊ के बगल उन्नाव में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। जिसमे एक लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सकता है। यूँ नोएडा में एक फिल्म सिटी पहले से बनी है, पर जिस उद्देश्य से बनी वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि उस फिल्म सिटी में फिल्मे बनने के बजाय धीरे–धीरे वहां न्यूज चैनलों का कब्जा होता चला गया। फिल्म निर्माता बोनी कपूर प्रदेश के पश्चिमांचल में 250 करोड़ रुपये लगाकर एक फिल्म स्टूडियो बनायेंगे, जिससे कोई 6 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। के.वी.एन. मूर्ती की एसोसिएटेड ब्राडकास्टिंग कंपनी 300 करोड़ की लागत से नोएडा में टीवी 9 मीडिया स्टूडियो

खोलना चाहते हैं, जिसमे अपलिंक और डाउनलिंक सुविधा होगी और कंटेंट प्रोडक्शन का काम किया जायेगा। इस परियोजना से भी 1,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

ए–ए यूनिवर्सल स्ट्रेटजिक कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मुकेश बहादुर सिंह 11 करोड़ की लागत से मध्यांचल क्षेत्र के लिए लखनऊ में द्विभाषी टीवी चैनल शुरू करेंगे। अनुमान ऐसा है कि इससे 100 लोगों को रोजगार मिल सकता है। मेधाज टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड ने 200 करोड़ की लागत से लखनऊ में मल्टीप्लेक्स बनाने का करार किया है। रूपा पब्लिकेशन्स के कपिश मेहरा गौतम बुद्ध नगर में डिजिटल पब्लिशिंग यूनिट लगाने का एम ओ यू साइन कर चुके हैं, जिससे 200 रोजगार सृजित हो सकते हैं। मार्किट टाइम्स के सुरेश मनचंदा नोएडा में 20 करोड़ का निवेश करके ऑनलाइन मार्केटिंग का काम शुरू करेंगे और इसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलने की आशा है. जयश्री माधव क्रिएशन की एम.डी. कंचना अवस्थी फिल्म निर्माण में 110 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं। मार्किट टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड की रूपा मेहता और बिग बेंग मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड की मधु मंतेना भी फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में पश्चिमांचल में 100–100 करोड़ रुपये का वादा कर चुकीं हैं। कृष्णा फिल्म्स के मालिक अमित कृष्ण श्रीवास्तव फिल्मों की शूटिंग पर 10 करोड़ रुपये लगाने को तैयार बैठे हैं। फेथ फिल्म्स की रौशनी श्रीवास्तव लखनऊ में और विजन एयर के इंद्र कुमार मिश्रा सुल्तानपुर में फिल्म निर्माण पर 5–5 करोड़ रुपये लगायेंगे। आलमाईटी इन्फोमेडिया के दिनेश गौतम ने एक करोड़ रुपये नॉएडा में मैगजीन पब्लिशिंग और रॉयल फेम प्रोडक्शन वर्ल्ड एक करोड़ रुपये फिल्म स्टूडियो और अकैडमी में निवेश करना चाहते हैं।

योगी सरकार ने जो परिवेश तैयार किया यह उसी का नतीजा है कि फिल्म और टीवी उद्योग में कुल मिलाकर दस हजार करोड़ रुपये के निवेश के सहमति–पत्रों पर हस्ताक्षर हो सके। उम्मीद है कि इन प्रयासों से न केवल यू.पी. के भातखंडे विश्वविद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी, आर्ट्स कॉलेज या दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकली प्रतिभाओं को अपनी ही जमीन पर निखारने का अवसर मिल सकेगा बल्कि करीब एक लाख लोगों को रोजगार के अवसर मुहैय्या हो सकते हैं।

विभिन्न नीतियाँ

'उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017'

- खनन नीति का मुख्य उद्देश्य खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक सतत् विकास, खनिजों का संरक्षण तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय का संतुलन बनाए रखना है।
- खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3 प्रतिशत किया जाएगा।
- अवैध खनन व परिवहन पर तकनीकी के प्रयोग से नियंत्रण एवं इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- खनिज सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाते हुए खनिज उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित किया जाएगा। ई–टेण्डरिंग, ई–ऑक्शन एवं ई–बिडिंग की प्रणाली को लागू किया जाएगा।

उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017'

- 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017' का दृष्टिक्षेत्र राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
- इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना है।
- इस हेतु मेगा परियोजनाओं को पुनः परिभाषित करते हुए निवेश को रोजगार सृजन के साथ लिंक किया गया है।
- मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाने हेतु प्रदेश में एक समर्पित 'मेक इन यू.पी.' विभाग की स्थापना की जाएगी।
- इस नीति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से प्रदेश का चहुंमुखी औद्योगिक विकास का सुनिश्चित किया जायेगा।

उ.प्र. नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017

- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नये रूट्स का विकास करके एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- एयर कार्गो हब के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जनसामान्य को रियायती दरों पर वायु सेवा के अवसर का लाभ मिलेगा।

उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
- फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड पार्क एवं कोल्ड चेन सुविधा का विकास किया जाएगा।
- रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराते हुए मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि होगी।

नवीन सौर ऊर्जा नीति–2017

- सौर ऊर्जा नीति–2017 जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में 10,700 मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्र की स्थापना हेतु 15,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 30,000 रुपये अनुदान प्रति विद्युत उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त होगा।
- सोलर पार्कों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन दिये जाएंगे।

उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति–2017

- प्रति एकड़ भूमि न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रतिकर्मी 15,000 रुपये की दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की एम.एस.एम.ई. की इकाइयों को व्यवसायिक परिचालन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेण्टल चार्जेज़ के 25 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति तथा विद्युत बिलों में

25 प्रतिशत उपादान, जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी, अनुमन्य होगी।

- स्टार्टअप कॉर्पस फण्ड की सीमा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये की गयी।

उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति–2017

- देश–विदेश की प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की इकाइयों की वृहद स्तर पर स्थापना के लिए सम्पूर्ण नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को 'इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' (ई.एम.ज़ेड.) घोषित किया गया।
- निजी क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ई.एस.डी.एम.) पार्क की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- ई.एस.डी.एम. के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित कर वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किये जाएंगे।

उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2017

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) सेक्टर में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
- इकाइयों की स्थापना हेतु सस्ती दरों पर भूमि की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी।
- प्रत्येक जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए 'एक जनपद, एक उत्पाद' की अवधारणा विकसित की जाएगी।

उ.प्र. हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेण्टिंग पॉलिसी–2017

- पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड एवं मध्यांचल में इस सेक्टर के विकास के लिए विशेष प्राविधान किये गये हैं।
- मेगा एवं सुपर मेगा वस्त्र उद्योग इकाइयों को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इसके माध्यम से लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

- नीति का मुख्य उद्देश्य खादी एवं ग्रामोद्योग की इकाइयों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का समुचित दोहन कर ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करना है।
- इसके अतिरिक्त जनपदों के विशिष्ट उत्पाद जो कि 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना से आच्छादित है, को जन सामान्य तक पहुंचाना, उनकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कराना तथा उनके विपणन में सहायता करने हेतु यह नयी नीति प्रस्तावित की गयी है।
- नीति के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु सहज और अनुकूल वातावरण के साथ युवाओं में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।

उ.प्र. पर्यटन नीति–2018

- राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को 'उद्योग' का दर्जा दिया है।
- इस नीति के माध्यम से पर्यटन विभाग का घरेलू पर्यटकों के आगमन में 15 प्रतिशत और विदेशी पर्यटकों में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है।
- नीति के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 हेरिटेज भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने का लक्ष्य।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैण्ड बैंक का सृजन करेगा।
- पर्यटन क्षेत्र में उद्यामियों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी का प्राविधान।

उत्तर प्रदेश फिल्म नीति–2018

- उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देते हुए निर्माताओं को हर सम्भव सहायता दी जाएगी।
- नीति के अन्तर्गत हिन्दी एवं उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ही प्रदेश में बनने वाली अंग्रेजी एवं देश की अन्य भाषाओं की फिल्मों को भी अनुदान की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जिससे प्रदेश में बनने वाली फिल्मों की संख्या में वृद्धि होगी।
- नीति के अन्तर्गत आकर्षक अनुदान से फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

उ.प्र. वेअरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति–2018

- इस नीति का लक्ष्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 की पूरक के रूप में राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सुदृढ़ करना है।

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :–

खादी, ग्रामोद्योग विकास व सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

प्रदेश में ग्रामोद्योगों के विकास हेतु तथा इन ग्रामोद्योगों के विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 'खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति' बनायी गयी है। नीति का मुख्य उद्देश्य खादी एवं ग्रामोद्योग की इकाइयों में पूजी निवेश को बढावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का समुचित दोहन कर ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करना है। इसके अतिरिक्त जनपदों के विशिष्ट उत्पाद जो कि 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना से आच्छादित है, को जन–सामान्य तक पहुचाना, उनकी गुणवत्ता बेहतर सुनिश्चित कराना तथा उसके विपणन में सहायता करने हेतु यह नयी नीति प्रस्तावित की गयी है। नीति के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु सहज और अनुकूल वातावरण के साथ युवाओं में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामोद्योगों के माध्यम से कुशन और अकुशल श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरोजगार सृजित होगा। देश में किसी भी प्रदेश द्वारा केवल ग्रामोद्योगों के विकास के लिए बनाये जाने वाली यह पहली नीति है तथा यह सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने की प्राथमिकता दर्शाती है।

रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम की मार्ग निर्देशिका में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर

गत् वित्तीय वर्ष 2016–17 में नेशनल लाइवस्टाक मिशन के अर्न्तगन "रूरल पोल्ट्री डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (60 प्रति के.पो.)" योजना के अर्न्तगत 251 मदर यूनिट की स्थापना हेतु मा0 मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से शासनादेश संख्या–2788/सैंतीस–2–2016–1(22)/टीसी दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा मार्ग निर्देशिका (गाइडलाईन्स)/कार्य योजना जारी की गयी थी। उक्त गाइडलाईन्स के प्रस्तर–4 अंकित है कि "01 मदर यूनिट से 300 चयनित बी.पी.एल. लाभार्थी" ही अंकित है। वर्तमान में इन्टरनेट पर उपलब्ध बी.पी.एल. लाभार्थियों के चयन में समस्या हो रही है। वर्ष 2011 में Socio Economic Caste Census (SECC-2011) किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (एल.पी.जी. गैस कनेक्शन) में बी.पी.एल. लाभार्थियों का चयन SECC-2011 की सूची से किया जा रहा है। अतः रूरल पोल्ट्री डेवलेपमेन्ट योजना में बी.पी.एल. लाभार्थियों के चयन में बी.पी.एल.–2002 की सूची में उपलब्ध बी.पी.एल. परिवारों के साथ–साथ की सूची में उपलब्ध बी.पी.एल. परिवारों को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत मदर यूनिटों की स्थापना की जाती है, जिनके माध्यम से योजनान्तर्गत बी.पी.एल. लाभार्थियों को लोइनपुट के चूजे उपलब्ध कराये जायेंगे। जनपद गाजियाबाद राजधानी दिल्ली से लगा 04 ब्लॉक का छोटा जनपद है जिसका अधिकांश क्षेत्र नगरीय/अर्द्धनगरीय होने के कारण लक्ष्य के अनुरूप बी.पी.एल. के पात्र लाभार्थियों के चयन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है तथा उक्त क्षेत्रों मे पोल्ट्री फार्मिंग हेतु कुक्कुट पालकों को बायोसिक्योरिटी मापदंड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नगर निगम/परिषद एवं एन.जी.टी. आदि नियमों एवं उप नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदर यूनिटों की स्थापना करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार की परिस्थितियां जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं बागपत में भी है।

अतएव उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2788/सैंतीस–2–2016–1 (22)/टीसी दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा मार्ग निर्देशिका (गाइडलाईन्स)/कार्य योजना में विहित व्यवस्था को अधोलिखित सीमा तक संशोधित किये जाने हेतु मा. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हैः–

1. मेरठ मण्डल के जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर एवं बागपत जनपदों को आवंटित लक्ष्यों को संशोधित करते हुये जनपद गाजियाबाद हेतु लक्ष्य शून्य, जनपद गौतमबुद्ध नगर हेतु 03 तथा बागपत हेतु 05 मदर यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाये।

2. जनपद गाजियाबाद के 10, गौतमबुद्ध नगर के 07 एवं बागपत के 05 इस प्रकार कुल अवशेष 22 मदर यूनिटों की स्थापना के लक्ष्यों को प्रदेश के अन्य जनपदों यथा जनपद इलाहाबाद हेतु 03 यूनिट, प्रतापगढ़ हेतु 03 यूनिट, कौशाम्बी हेतु 05 यूनिट, फतेहपुर हेतु 03 यूनिट, बरेली हेतु 03 यूनिट व बदायूँ हेतु 05 यूनिट को आवंटित कर दिया जाये।

3. योजना में बी.पी.एल. लाभार्थियों के चयन में बी.पी.एल. –2002 की सूची में उपलब्ध बी.पी.एल. परिवारों के साथ–साथ Socio Economic Caste Census (SECC-2011) की सूची में बी.पी.एल. परिवारों को भी सम्मिलित किया जाये।

चूंकि योजना पर पूर्व में मा. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है तथा सम्प्रति प्रथम संशोधन भी मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त किया जाना प्रस्तावित है। अतएव योजना के निर्बाध रूप से संचालन व समय की बचत के दृष्टिगत यह भी प्रस्तावित है कि भविष्य में नेशनल लाइवस्टाक मिशन के अर्न्तगत "रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (60 प्रति के.पो.)" योजना की गाइडलाईन्स/कार्ययोजना में किसी प्रकार के परिमार्जन/संशोधन की आवश्यकता होने पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु मा. मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को वाणिज्य कर विभाग में संविलीन किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित

प्रदेश में 01 जुलाई 2017 से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रवृत्त हो जाने और मनोरंजन कर का, माल और सेवा कर में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग में नियुक्त/संविलीन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सेवानिवृत्त सैन्य पेंशनरों के राज्य सरकार के सिविल पदों में पुनर्योजन पर वेतन निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदित

सेवानिवृत्त सैन्य पेंशनरों के राज्य सरकार के सिविल पदों पर पुनर्योजन पर वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय पेंशन की राशि में अधोलिखित सीमा तक संशोधन किया गया हैः–

01 55 वर्ष की आयु के पूर्व सेवानिवृत्त सैन्य पेंशनर, जो राज्य सरकार के अधीन पुनर्योजित हैं, के वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय पेंशन की राशि दिनांक 01–01–2006 से

रू. 1500/– से बढ़ाकर रू. 4,000/– की गयी थी।

02 भारत सरकार द्वारा सिविल पदों पर पुनर्योजित भूतपूर्व कमीशन्ड रैंक के सैन्य अधिकारियों की उपेक्षणीय पेंशन की धनराशि कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3/3/2016 Estt. (पे.-II), दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा दिनांक 01–01–2016 से रू. 4,000/– से बढाकर रू. 15,000/– कर दी गयी है।

03 भारत सरकार द्वारा लागू उपरिलिखित व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा भी अंगीकृत करते हुये, 55 वर्ष की आयु के पूर्व सेवानिवृत्त सैन्य पेंशनरों तथा सेवानिवृत्त के समय समूह 'क' के पदों पर कार्यरत रहे सिविलियन अधिकारियों द्वारा उ.प्र. सरकार की सेवा में पुनर्योजित होने पर उनके वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय पेंशन की राशि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से रू. 4,000/– से बढाकर रू. 15,000/– की जा रही है। उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी।

परिषदीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

वित्तीय वर्ष 2017–18 से परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र 02 सेट निःशुल्क यूनीफार्म, पाठ्य–पुस्तक, निःशुल्क स्कूल बैग तथा मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है। उक्त छात्र–छात्राओं को 01 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप उनमें उत्साह वर्धन होगा और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के प्रति आकर्षित होंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांश बच्चे अल्प आय वर्ग से शिक्षा प्राप्त करने आते है। अतएव परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–1 से 5 एवं 6 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को ठंड से बचाव के लिए निःशुल्क 01 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

स्वेटर का वितरण प्रत्येक दशा में दिनांक 06–01–2018 से प्रारम्भ किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/विद्यालय प्रबंध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक विद्यालय में स्वेटर वितरण मा. सांसद, मा. विधायक एवं अन्य मा. जनप्रतिनिधिगण से सम्पर्क कर वितरण की तिथियों से अवगत कराया जायेगा तथा यह भी प्रयास किया जायेगा कि वितरण मा. जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में हो। स्वेटर का वितरण ग्राम प्रधान एवं बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाये।

विकास खण्ड/वार्ड स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वेटर के वितरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी यह भी प्रमाणित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी विद्यालयों में क्रय प्रक्रिया सही अपनायी गयी है तथा समस्त भुगतान 'एकाउन्ट पेई' चेक के माध्यम से किये गये है। यदि किसी प्रकार किसी स्तर पर स्वेटर की आपूर्ति में खण्ड शिक्षा अधिकारी की संलिप्तता पायी जाती है अथवा शिकायतें प्राप्त होती हैं तो विभाग द्वारा उसे संज्ञान में लेते हुए न केवल रिकवरी की कार्यवाही की जायेगी, अपितु उसे कदाचार की श्रेणी में रखते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से यथा निर्देश स्वेटर वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगें। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में विद्यालय प्रबंध समिति स्तर तक की योजना बनायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्तर पर 'कम्यूनिकेशन–गैप' न हो।

किसी भी स्तर पर स्वेटर की गुणवत्ता खराब पाये जाने पर अथवा फर्जी संख्या दर्शाकर वास्तविकता से अधिक वितरण दिखाने पर तथा नकद भुगतान करने आदि से सम्बन्धित शिकायतें सही पाये जाने पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही कर उनके अधिक व्यय धनराशि की वसूली करायी जायेगी तथा प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक/खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध दण्ड दिये जाने की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। इस संबन्ध में मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से शासनादेश दिनांक 03–01–2017 को निर्गत कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जूता, मोजा एवं स्वेटर के लिये एकमुश्त धनराशि रू. 300 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध थी, जिसके सापेक्ष मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से जूता एवं मोजा हेतु रू. 266 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है तथा रू. 34 करोड़ अवशेष है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू. 3,90,03,27,000/– का बजट प्रावधान अनुपूरक बजट के माध्यम से कराया गया है। इस प्रकार वर्तमान में स्वेटर हेतु रू. 4,24,03,27,000/– की धनराशि उपलब्ध है। जिसके दृष्टिगत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू.

1,54,23,00,000/– (एक अरब चौवन करोड़ तेईस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–19/79–5–2018, दिनांक 05.01.2018 द्वारा निर्गत कर दिया है।

उ.प्र. बेसिक शिक्षा ‹अध्यापक› सेवा नियमावली–1981 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर

रिट याचिका संख्या–47490/2017 कु. पल्लवी बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.11.2017, 18.11.2017 तथा 27.11.2017 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के न्यूनतम अर्हता के संम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 23.08.2010, 29.07.2011 एवं 12.11.2014 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के रेगुलेशन–9 (यथा संशोधित) अधिसूचना दिनांक 28.11.2017 के एपेडिक्स–2 की प्रस्तावना 1.2 में निर्धारित प्रशिक्षण अर्हतायें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ मान्य किया गया है तथा इसके साथ भविष्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रशिक्षण अर्हता के संबंध में समय–समय पर निर्गत अधिसूचनायें यथावत मान्य किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

उ.प्र. बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–1981 में उक्त अर्हताओं को सम्मिलित किये जाने हेतु नियमावली के नियम–8 व 14 में 21वां संशोधन प्रस्तावित हैं।

आबकारी विभाग में ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली को लागू करने का निर्णय

मदिरा की तस्करी रोकने तथा राजस्व की सुरक्षा हेतु वर्ष 2000–2001 से प्रत्येक मदिरा बोतल पर सुरक्षा होलोग्राम लगाने का निर्णय लिया गया था। तब से आज तक प्रदेश में विक्रय की जा रही मदिरा की समस्त धारिता एवं तीव्रता की बोतलों पर सुरक्षा होलोग्राम चस्पा किये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान होलोग्राम आपूर्तक का कार्यकाल दिनांक 18.06.2013 से 03 वर्ष अर्थात् दिनांक 17.06.2016 था, जिसे संविदा/अनुबन्ध शर्तों के अनुसार उन्हीं शर्तों एवं दरों पर अधिकतम आगामी दो वर्षो के लिये अर्थात् दिनांक 17.06.2018 तक बढ़ाया जा सकता है। नये होलोग्राम आपूर्तक के चयन हेतु दिनांक 22.09.2016 को निविदा आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदा मे. यू–फ्लैक्स लि. द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम पाये जाने के आधार पर इसे आपूर्तक के रूप में चयन करने हेतु शासनादेश दिनांक 15.12.2016 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2– मा. वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता मे सम्पन्न वित्त संसाधन समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में अन्य राज्यों में लागू बार कोड व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। मा. आबकारी मंत्री जी के निर्देशानुसार नवीन उन्नत तकनीकी के समावेश हेतु आयुक्तालय स्तर पर एक समिति गठित की गई। समिति ने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली का अध्ययन किया गया तथा अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा होलोग्राम के स्थान पर नवीन तकनीकी व्यवस्था लागू किये जाने की सिफारिश की गई, जिसके आलोक में वर्ष 2016 में होलोग्राम आपूर्ति हेतु चयनित मे. यू–फ्लैक्स लि. के चयन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– वर्तमान में प्रति इकाई सुरक्षा होलोग्राम की अनुमानित कीमत लगभग 37 पैसा है, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सस्ती दरों पर भी नवीन तकनीक उपलब्ध है, जिसके माध्यम से प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक इकाई की वास्तविक वस्तुस्थिति यथा उत्पादन से लेकर उपभोग तक का आकलन किया जाना सम्भव है। प्रवर्तन कार्य में फर्जी होलोग्राम के प्रकरण पाये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत आबकारी नीति 2018–19 में होलोग्राम के स्थान पर मदिरा उत्पादन एवं निकासी की व्यवस्था को इलेक्ट्रानिक माध्यम से ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली द्वारा नियंत्रित किये जाने की व्यवस्था की गई है। अतः पूर्व में प्रचलित होलोग्राम व्यवस्था को निरस्त करने तथा आपूर्तक की जमानत धनराशि को वापस करने का निर्णय लिया गया है। ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली का साफ्टवेयर एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश के द्वारा विकसित कर इस प्रयोजन को क्रियान्वित किया जाएगा।

केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग/संस्था/प्राधिकरण/निगम आदि की निर्माण परियोजनाओं के लिए मिट्टी के खनन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में

उ.प्र. उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 (यथासंशोधित) नियमावली में सामान्य मिट्टी (साधारण मिट्टी) उपखनिज के रूप में सम्मिलित है। वर्तमान में उक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम 06 माह के लिए सामान्य मिट्टी के खनन हेतु अनुज्ञा–पत्र (परमिट) निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं। जिलाधिकारी द्वारा खनन योजना स्वीकृत करने और यथावश्यक पर्यावरणीय अनापत्ति निर्गत करने के उपरांत सामान्य मिट्टी के लिए अनुज्ञा–पत्र निर्गत किया जाता है।

सामान्य मिट्टी के लिए भूमिधर की सहमति, खनन योजना, पर्यावरण अनापत्ति आदि प्राप्त करने के कारण खनन अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति के समय लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का कार्य बाधित होता है। परियोजनाओं में साधारण मिट्टी कार्य प्रथम चरण का कार्य होता है, जिसकी पूर्णता के उपरांत ही परियोजना को गति प्रदान की जा सकती है।

उ.प्र. खनिज (परिहार) नियमावली, 1960 के नियम–68 में विशेष मामलों में राज्य सरकार को नियमों को शिथिल किए जाने की शक्ति प्रदान की गयी है। उक्त प्राविधान के अन्तर्गत केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग/संस्था/प्राधिकरण/निगम आदि जैसे एन.एच.ए.आई., डी.एफ.सी.सी.आई., यूपीडा, रेलवे/लोक निर्माण विभाग को आदि द्वारा संचालित एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत परियोजनाओं हेतु साधारण मिट्टी के खनन के सम्बन्ध में खनन योजना स्वीकृत कराये जाने से छूट प्रदान करते हुए जनपदवार मिट्टी की वांछित मात्रा एवं प्रतिमाह निकाली जाने वाली मिट्टी की मात्रा का विवरण उपलब्ध कराये जाने पर, साधारण मिट्टी की देय रायल्टी की दर पर जिलाधिकारी द्वारा एक बार में अधिकतम 01 वर्ष के लिए अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

निजी भूमि के सम्बन्ध में भू–स्वामी की सहमति तथा सार्वजनिक/गाँव सभा की भूमि से सक्षम स्तर की अनुमति के बिना खनन कार्य नहीं किया जा सकेगा। साधारण मिट्टी के खनन के सम्बन्ध में मा. मंत्रिपरिषद के लिए प्रस्तुत टिप्पणी के प्रस्तर–5 में उल्लिखित अन्य शर्तें प्रभावी होंगी।

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण हेतु प्रस्तावित योजना को मंजूरी

प्रदेश में प्रति वर्ष फसलों में कीट रोग तथा खरपतवारों आदि द्वारा लगभग 15 से 20 प्रतिशत क्षति होती है। फसलों में होने वाली क्षति को कम किए जाने के दृष्टिगत वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण हेतु रू. 155.90 करोड़ की योजना प्रस्तावित की जा रही है। योजनान्तर्गत कीट/रोग के प्रकोप के सर्विलेंस, सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली एवं आई.पी.एम. एवं कृषि रक्षा की नई तकनीकी की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं।

पर्यावरण संरक्षण व विषरहित खाद्यान्न उत्पादन के लिए बायोपेस्टीसाइड्स तथा बायोएजेन्ट्स 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे। कृषि विभाग द्वारा 09 आई.पी.एम. प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनके द्वारा बायोपेस्टीसाइड्स यथा–ट्राइकोडरमा, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन.पी.वी. आदि एवं बायोएजेन्ट्स यथा–ट्राइकोडरमा कार्ड का उत्पादन किया जा रहा है। खरपतवार/कीट/रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन प्रणाली (आई.पी.एम.) को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीज जनति रोगों के नियंत्रण हेतु 75 प्रतिशत अनुदान पर बीज शोधक रसायन कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

लघु एवं सीमान्त कृषक को खरपतवार/कीट/रोग के नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनों को 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को फुट स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि कृषि रक्षा यंत्रों एवं सुरक्षित अन्न भण्डारण हेतु बखारियों का वितरण 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध करया जाएगा।

उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन के सम्बन्ध में

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा–77 में संशोधन से पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना, डेडीकेट फ्रंट कॉरीडोर परियोजना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस–वे परियोजना जैसी सरकार की महात्वाकांक्षी परियोजनाओं हेतु आरक्षित श्रेणी की भूमियों के पुनर्ग्रहण/विनिमय में सहजता आ सकेगी।
2. धारा–80 में संशोधन से कृषि भूमि के औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजन हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम हो सकेगी।
3. धारा–89 (3) में संशोधन से विहित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु अनुमति की प्रक्रिया सहज हो सकेगी, जिससे औद्योगिकीकरण तथा प्रदेश के विकास की गति तेज हो सकेगी।
4. धारा–94 व धारा–95 में संशोधन से कृषि योग्य भूमियों के पट्टे पर दिए जाने से कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि पट्टे पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे प्रदेश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।
5. धारा–108 व धारा–110 में संशोध्न से पैतृक भूमि में मृतक पुत्र के अविवाहित पुत्रियों को अधिकार मिल सकेगा।

फोटो फीचर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शास्त्री भवन में पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमण्डल भेंट करते हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शास्त्री भवन में केन्द्रीय पर्यटन सचिव के साथ बैठक के दौरान
कुंभ का प्रतीक-चिन्ह भेंट करते हुए

फोटो फीचर

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, सूरजकुंड (फरीदाबाद) हरियाण में उ.प्र. और हरियाणा सरकार के बीच पारस्परिक परिवहन अनुबंध हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर।

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनपद रामपुर में 'सामाजिक अधिकारिता शिविर एवं निःशुल्क सहायक' उपकरण वितरण समारोह में दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग विरण कार्यक्रम अवसर पर

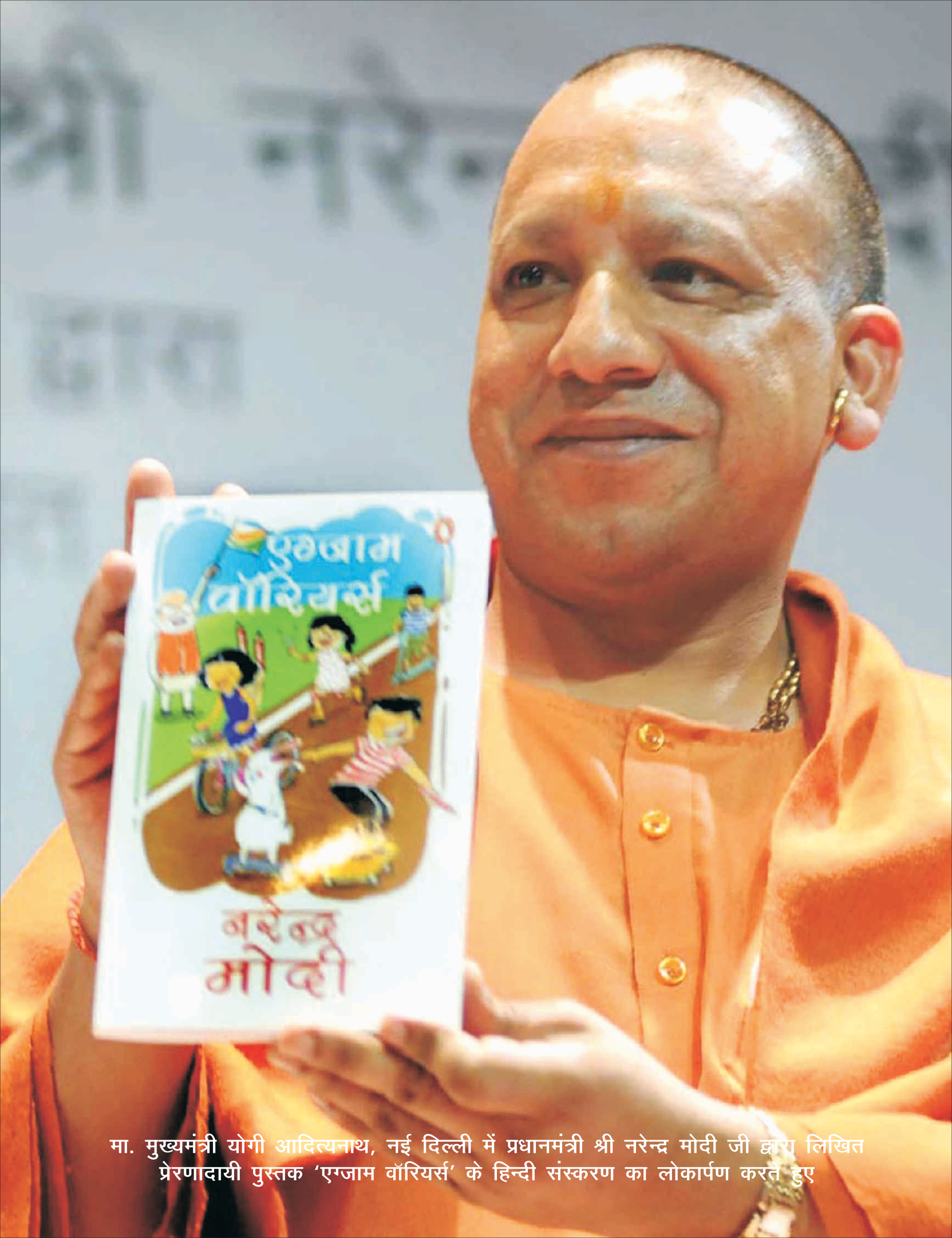

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लिखित प्रेरणादायी पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' के हिन्दी संस्करण का लोकार्पण करते हुए